

मुकदमों का विवरण

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम

मेसर्स तिरुमाला निर्माण (सिविल अपील संख्या)।1628 20 अक्टूबर, 2023)

[एस. रवींद्र भाट और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कराधान के संवैधानिक आधार का एक मौलिक पुनर्निर्धारण प्रस्तुत करता है। यह वस्तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) को लागू करने के लिए एक रूपरेखा है। अपीलों का यह समूह तेलंगाना, गुजरात और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से उत्पन्न होता है। संबंधित राज्यों (तेलंगाना और गुजरात) ने इन फैसलों से व्यथित होकर अपील की है। निर्धारिती याचिकाकर्ता अपीलार्थी हैं, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों से व्यथित हैं।

भारत का संविधान-संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016-इसका प्रभाव:

आयोजित किया गया:जी. एस. टी. व्यवस्था के लागू होने और संशोधन के पारित होने से यह सुनिश्चित करने के लिए एक दुर्लभ सर्वसम्मति, राजनीतिक स्पेक्ट्रम में एक संकल्प का प्रदर्शन होता है कि एक एकल अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था हो-संशोधन का प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं पर सभी राज्य और केंद्र करों को शामिल करना है-केंद्र और राज्य दोनों के पास वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने की शक्ति होगी-101 वां संशोधन अधिनियम न तो केंद्र की और न ही राज्यों की कर लगाने की शक्ति को छीनता है, बल्कि उन्हें क्रमशः वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने की शक्ति देता है-अनुच्छेद 246-ए के माध्यम से संशोधन बनाता है:(क) एक नया विधायी निकाय, जो प्रदान करता है; (ख) सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों के बाहर विधायी प्राधिकरण; (ग) संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को एक ही विषय पर और एक ही समय में विधान बनाने की समवर्ती शक्तियाँ।

141

[पैरा 8] 142 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

भारत का संविधान-संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 -एस. 19-की व्याख्या:

आयोजित किया गया:धारा 19 तीन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है-पहला, राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के संबंध में मौजूदा स्थिति को बनाए रखना, संशोधन शुरू होने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए या जब तक कोई नया कानून लागू नहीं किया जाता है, जो भी पहले हो-दूसरा, सक्षम विधानसभाओं यानी राज्य विधानमंडलों और संसद को उन मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिए अधिकृत करना है जो राज्यों और देश के अन्य हिस्सों (केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों) में लागू थे-तीसरा ऐसे कानूनों का निरसन था-धारा 19 संक्रमणकालीन था-इसके

अभाव में, कई सैकड़ों राज्य अधिनियम और केंद्रीय कानून जो लागू थे, खतरे में पड़ जाते।¹⁹ कोई बचत प्रावधान नहीं है जो संशोधन का हिस्सा है-इसलिए, संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 19 और घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित अनुच्छेद 246 ए, इसके संचालन की सीमित अवधि के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था का हिस्सा थे, और इसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि (ओं) के लिए असंगत कानूनों के संचालन को जारी रखने का प्रभाव था और इसके संचालन के आधार पर, राज्य विधानसभाओं और संसद को ऐसे मौजूदा कानूनों में संशोधन या निरसन करने की अनुमति दी गई थी।[पारस 73,116]

भारत का संविधान-सामान्य कानून और संवैधानिक कानून:

आयोजित किया गया: संसद के अधिनियम जैसे साधारण कानून, एक विधायी अभ्यास का एक उत्पाद है-उस शक्ति का स्रोत संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों में या एक या दूसरी सूचियों में सूचीबद्ध विधान के माध्यम से पाया जाता है-दूसरी ओर संवैधानिक कानून यह है कि यह संविधान से उत्पन्न होता है और राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है, उनकी शक्तियों की अवहेलना करता है और मौलिक अधिकारों और अन्य सीमाओं के माध्यम से कार्यकारी और विधायी शाखाओं के कामकाज पर सीमाएं लगाता है-एक साधारण कानून एक ही निकाय द्वारा बनाया या बदला जा सकता है, विधायी शक्ति का प्रयोग करने में विधायी निकाय-क्योंकि संवैधानिक संशोधन देश के मौलिक कानून से संबंधित हैं जो अन्य कानूनों के लिए अधिकार का स्रोत है, इसे केवल पूर्ण करने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।[पैरा 77]

भारत का संविधान-संविधान **(101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 -एस. 19-**क्या संशोधन या निरसन की शक्ति यू/एस की सीमाओं के अधीन है।**19:**

143

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला निर्माण

आयोजित किया गया: यू/एस की कोई सीमा नहीं थी।¹⁹ (संशोधन के अनुच्छेद 246 ए के साथ पठित)-यह प्रावधान मौजूदा कानूनों में संशोधन के माध्यम से आवश्यक परिवर्तन करने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए उपलब्ध संप्रभु विधायी शक्ति की अभिव्यक्ति का गठन करता है-जैसा कि राम कृष्ण रामनाथ मामले में माना गया है कि संक्रमणकालीन शक्ति (उस मामले में, धारा 143 (3)) "इसके निहितार्थ से प्रावधान एक सीमित विधायी शक्ति प्रदान करता है जो लेवी को जारी रखने की इच्छा या इच्छा नहीं करता है"-यह सीमित विधायी शक्ति राज्यों द्वारा कथित तरीके से संकुचित या सीमित नहीं थी। यह इंगित समय सीमा (यानी एक वर्ष, या नया जी. एस. टी. कानून अधिनियमित होने तक) द्वारा सीमित है-इसलिए, यह संशोधित संविधान के अनुरूप मौजूदा प्रावधानों को लाने के अलावा अन्य प्रावधानों को अधिनियमित कर सकता है-क्योंकि उक्त संशोधन अधिनियम के अन्य प्रावधानों में, सूची I और सूची II (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची) से कानून के शीर्षों को हटाने का प्रभाव था, दोनों धाराएँ।¹⁹ और Art.246A ने घटक अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित किया कि मौजूदा कानून जारी रहेंगे और उनमें संशोधन किया जा सकता है-कानून के स्रोत या अन्य तथ्य, जिस हद तक उन्हें दोनों सूचियों से हटा दिया गया था, कुछ समय

के लिए, एस में निहित थे।¹⁹ – नतीजतन, संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी।[पैरा 97 और 116]

भारत का संविधान-संविधान **(101 वां संशोधन)** अधिनियम, **2016**-तेलंगाना अधिनियम की वैधता का परीक्षण एक अध्यादेश के रूप में इसके उद्भव के स्पर्श पत्थर से किया गया:

आयोजित किया गया:तेलंगाना अध्यादेश 17.6.2016 पर जारी किया गया था-तेलंगाना राज्य जीएसटी अधिनियम लागू किया गया था और 25.05.2017 पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त की गई थी; इसे आई. डी. 1 पर लागू किया गया था-राज्य जी. एस. टी. अधिनियम में एक बचत और निरसन कानून शामिल था, जिसमें निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित कार्यों, विशेषाधिकारों और अधिकारों को बचाने की मांग की गई थी, यानी राज्य वैट अधिनियम-यह तर्क दिया गया था कि एक बार राज्य विधानमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी और इसके अनुरूप संशोधन को लागू कर दिया, तो अध्यादेश के प्रावधान अधिनियम का हिस्सा बन गए-विधायी क्षमता का सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि एक अध्यादेश का केवल अधिकार राज्य विधानमंडल की क्षमता के भीतर है-क्योंकि कानून को एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया गया था, यानी अध्यादेश, उस कानून का प्रभाव, जो वैट अधिकारियों को फिर से खोलने या पूरा करने का अधिकार देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

उन्होंने समझाया कि जब अध्यादेश जारी किया गया था, तो राज्य के विधायी क्षमता रखने के बारे में कोई संदेह नहीं था-उस तारीख (17.06.2017) तक मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की शक्ति, यू/एस की अनुमति थी।¹⁹ हालांकि, यह तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि अध्यादेश की वैधता और प्रभाव इसकी घोषणा की तारीख को संदिग्ध नहीं रहा होगा; फिर भी, मुद्दा यह है कि जिस तारीख को इसे वास्तव में अनुमोदित किया गया था और एक संशोधन के रूप में आकार दिया गया था, उस तारीख को राज्य विधानमंडल के पास शक्ति समाप्त हो गई थी-उस समय तक, राज्य जी. एस. टी. और केंद्रीय जी. एस. टी. अधिनियम (<आई. डी. 1 पर) लागू हो गए थे-इसलिए, धारा 19 प्रभावी नहीं रही थी-मूल प्रविष्टि (राज्य सूची की प्रविष्टि 54) का अस्तित्व समाप्त हो गया-इन परिस्थितियों में, राज्य विधानमंडल के पास संशोधन को लागू करने के लिए कोई विधायी क्षमता नहीं थी, जिसने अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसे परिणामस्वरूप अमान्य कर दिया गया था।[पारस 102,105]

भारत का संविधान-संविधान **(101 वां संशोधन)** अधिनियम, **2016**-गुजरात अधिनियम:

आयोजित किया गया:गुजरात के मामलों के समूह में,s.84A को गुजरात मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा गुजरात मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 में पेश किया गया था, जिसे 06.04.2018 पर राजपत्रित किया गया था, लेकिन 1.4.2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ-इसमें अन्य बातों के साथ यह प्रावधान किया गया था कि यदि "कुछ अन्य कार्यवाही" में किसी विशेष मुद्दे के लिए एक निचले मंच ने एक निर्णय दिया जो राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है और इस तरह के निर्णय के खिलाफ अपील उच्च मंच के समक्ष लंबित है, तो संशोधन के लिए सीमा की

अवधि की गणना करते समय इस तरह की मुकदमेबाजी में खर्च की गई अवधि को बाहर रखा जाएगा-इस तरह के प्रावधान को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर राज्य विधानमंडल ने इस तरह से आकलन को फिर से खोलने में सक्षम बनाने की मांग की, जो पहले ही वास्तविकता प्राप्त कर चुके थे-गुजरात उच्च न्यायालय ने कमी के आधार पर संशोधन को रद्द कर दिया।[पारस 16,113,116] 145

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला निर्माण

भारत का संविधान-संविधान **(101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016**-महाराष्ट्र अधिनियम:

आयोजित किया गया: जहां तक महाराष्ट्र की अपीलों का संबंध है, निर्धारिती की शिकायत यह है कि महाराष्ट्र वैट अधिनियम में किए गए पूर्वव्यापी संशोधन अमान्य थे-इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि एक विधायी निकाय पूर्वव्यापी प्रभाव वाले सुधारात्मक कानून को लागू करने के लिए सक्षम है-फिर भी, वही बुराई जो खुद को गुजरात संशोधन से जोड़ती है, यानी संशोधन लागू होने की तारीख को क्षमता की कमी, यानी इस मामले में, महाराष्ट्र विधानमंडल को विषय वस्तु पर कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि मूल प्रविष्टि 54 में पर्याप्त बदलाव हुआ था, और वैट अधिनियम को बदलने की शक्ति समाप्त हो गई थी, जब जीएसटी व्यवस्था प्रभावी हुई थी-इसलिए, उन्हीं कारणों से, जैसे कि [पैरा 15,115]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

रामकृष्ण रामनाथ बनाम जनपद सभा [1962] पूरक।(3) एससीआर 70; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य [1973] पूरक 1 एससीआर 1; कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य [2017] 5 एससीआर 160-इसके बाद आया।

सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस. वी.यू. पी. राज्य & अन्य [1989] पूरक (1) एससीआर 623; विपुलभाई एम. चौधरी बनाम गुजरात मिलक एमकेटीजी फेडरेशन लिमिटेड [2015] (3) एससीआर 997; बोंडू रामास्वामी बनाम बेंगलोर विकास प्राधिकरण [2010] 6 एससीआर 29; एल. आर. के माध्यम से बिमोलांगशु रॉय (मृत)। वी.असम राज्य और अन्य [2017] 13 एससीआर 301; ए. हाजी अब्दुल शकूर एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य [1964] 8 एससीआर 217; जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 813; केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड [1976] 1 एससीआर 552; भारत संघ बनाम मोहित खनिज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड [2018]

13 एस. सी. आर. 139-पर निर्भर।

टी. एन. कल्याण मंडपम एसोसिएशन बनाम भारत संघ [2004] पूरक 1 एस. सी. आर. 169; गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य [2005] 1 एससीआर 732; ए. के. रॉय बनाम यू. ओ. आई. [1982] 2 एस. सी. आर. 272; आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ [1982] 1 एस. सी. आर. 947; फुएस्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स

लिमिटेड [2001] 3 एस. सी. आर. 479; यू. ओ. आई. और ए. एन. आर. वी. मोहित
मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड [2022] 9 एस. सी. आर. 300; अनंत मिल्स कंपनी लिमिटेड
बनाम महाराष्ट्र राज्य [1975] 3 एस. सी. आर. 220; 146 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट
[2023] 15 एस. सी. आर.

विजय प्रकाश डी. मेहता बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), बॉम्बे [1988] सप्लीमेंट (2)
एससीआर 434; हरियाणा राज्य बनाम मारुति उद्योग लिमिटेड और अन्य। [2000] पूरक 3
एस. सी. आर. 185; तिरुमाली केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ [2011] 4 एस. सी.
आर. 739; नीना अनेजा और अन्न। वी. जय प्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड [2021] 15
एससीआर 96; मेसर्स वेस्ट रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम. मद्रास
राज्य [1963] 2 एस. सी. आर. 747; राजस्थान राज्य बनाम मंगीलाल पिंडवाल [1996]
पूरक (3) एस. सी. आर. 98; मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। भारत संघ [1996]
पूरक। (10) एस. सी. आर. 585; गुजरात राज्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2017]
13 एस. सी. आर. 25; सुंदरगढ़ जिला आदिवासी अधिवक्ता संघ और अन्य। बनाम ओडिशा
राज्य और अन्य [2013] 6 एस. सी. आर. 420; भारत संघ बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स
इंडिया (पी) लिमिटेड [2021] 15 एस. सी. आर. 169; आर. अब्दुल कादर बनाम बिक्री
कर कार्यालय [1964] 6 एस. सी. आर. 867; मध्य प्रदेश राज्य बनाम एम. वी. नरसिम्हन
[1976] 1 एस. सी. आर. 6; आर. के. गर्ग आदि। आदि बनाम भारत संघ और अन्य।
[1982] 1 एससीआर 947; गुजरात राज्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2017] 16
एससीसी 28; श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम। ब्रोच बरो नगर पालिका [1970] 1
एससीआर 388; आंध्र प्रदेश सरकार बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड [1975]
सप्लीमेंट (1) एससीआर 394; उजागर प्रिंट्स बनाम भारत संघ [1988] सप्लीमेंट 3
एससीआर 770; अंशुल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य एसटीए सं. 2/2018;
संयुक्त परियोजना बनाम महाराष्ट्र राज्य (लिखित याचिका)

(एसटी.) 2021 की सं. 11589 और 2018 की रिट याचिका सं. 13754; की स्थिति

गुजरात बनाम वेलस्पन गुजरात स्टाल रोरेन लिमिटेड [2014] 71 वीएसटी 550 (गुजरात);
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। गुजरात राज्य [2018] 58 जी. एस. टी. आर. 366
(गुजरात); श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड एलाइड केमिकल्स लिमिटेड बनाम आंध्र राज्य

प्रदेश और ओआरएस। 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन ए. पी. 1158-संदर्भित। भारत का संवैधानिक
कानून चौथा संस्करण खंड 3 पृष्ठ 3119; पृष्ठ 271 पर पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस लॉ
लेक्सिकन खंड I-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 1628/2021 के डब्ल्यू. पी. No.5010 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 03.08.2022 के निर्णय और आदेश से।

147

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला निर्माण के साथ

सी. ए. संख्या 2502-2513, 2644-2686, 2644-

2686, 2732, 2733, 1654, 1683, 1662, 1663, 1629, 1658, 1630, 1653, 1655, 1657, 1672, 1676, 1656, 1661, 1664, 1660, 1682, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1659, 2690, 1670, 1673, 1671, 1674, 1675, 1677, 2687, 2688, 2689 2023 एस. एल. पी. (सी) संख्या 7776, 13543-13545, 13529-13530, 13523-13526, 13547-13559, <आई. डी 3

रूप:

विक्रम नानकानी, अरविंद पी. दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता।, बी. एस. प्रसाद A.G./Sr. अधिवक्ता, सुश्री कविता झा, अर्नब रॉय, पृथ्वीराज चौधरी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, कुमार प्रशांत, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सुश्री मंजू जेटली, वरुण मिश्रा, अंकुर जैन, प्रब्लिन सिंह अब्रोल, संचित जैन, अनिरुद्ध सिंह, राजावत, अजय शर्मा, अवधेश कुमार, मंजू जेटली, दिगंत मिश्रा, सोमनाद्री गौड़ कटम, राहुल उन्नीकृष्णन, सिराजुद्दीन, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

बलबीर सिंह, ए. एस. जी., एस. द्वारकानाथ, सौरभ सोपारकर, कपिल सिब्बल, एस. गणेश, जय सावला, दामा शेषादारी नायडू, सीनियर एडवो., समीर जैन, सुश्री अनु सुरा, सोइब कुरैशी, के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, राजीव गुप्ता, विनय राजपूत, के. आर. शशिप्रभु, उचित शेठ, संतोष कृष्णन, विष्णु शर्मा ए. एस., प्रखर अग्रवाल, रॉबिन रत्नाकर डेविड, आर. जवाहरलाल, सिद्धार्थ बावा, अनुज गर्ग, मोहित शर्मा, मयंक क्षीरसागर, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री अदिति अनिल दानी, रजत श्रीवास्तव, आयुष, सुश्री सिमरान गुप्ता, आशुतोष झा, डॉ. एम. वी. के. मूर्ति, एम. वी. जे. के. कुमार, एम. कुमार, हितेंद्र नाथ रथ, मोहन राज ए, हरिहरन, सुश्री।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अभिषेक विकास, सुश्री तातिनी बसु, सुश्री नितिप्रिया कर, कुमार शशांक, बैरपानेनी सुयोधन, कृष्ण कुमार, श्रीमती नीतू शर्मा, नितिन पाल, शिवम पांडे, येलामंचिली शिव संतोष कुमार, रुद्रजीत घोष, तुषार अरोड़ा, तरुण गुप्ता, ईशान जॉर्ज, सुश्री शिवानी तुशीर, मेसर्स श्री चक्र चैबर्स, वेंकटराम रेड्डी मंतूर, जी. एन. रेड्डी, रविशंकर, वेदुमुदी विष्णु सी. कश्यप, उचित सेठ, मलक मनीष भट्ट, जसदीप

सिंह ढिल्लन, प्रभात कुमार चौरसिया, युगांतर सिंह चौहान, सुश्री पिकी बेहरा, रिज़वान अहमद, श्रीउत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश एस. रवींद्र भाट, जे.

सामग्री की तालिका

I. पृष्ठभूमि और प्रासंगिक प्रावधान। तथ्य. **9 III.** अपीलार्थी-राज्यों के तर्क। **11 IV.** प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं के तर्क. **20** वी. विश्लेषण और तर्क. **33** ए. धारा **19** की व्याख्या. **35** बी. क्या संशोधन या निरसन की शक्ति विषय है।

धारा **1940,149** के तहत सीमाओं के लिए

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 150

ग. तेलंगाना अधिनियम की वैधता का परीक्षण एक अध्यादेश के रूप में इसके उद्भव के स्पर्श पत्थर से किया गया। **50** डी. गुजरात और महाराष्ट्र अधिनियम. **57 VI।** निष्कर्ष. **63**

1. अपीलों का यह समूह तेलंगाना, गुजरात और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों से उत्पन्न होता है। संबंधित राज्यों (तेलंगाना और गुजरात) ने फैसलों से व्यथित होकर अपील की है। निर्धारित याचिकाकर्ता अपीलार्थी हैं, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों से व्यथित हैं।

I. पृष्ठभूमि और प्रासंगिक प्रावधान

2. संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016, (जिसे इसके बाद "संशोधन" के रूप में संदर्भित किया गया है) भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कराधान के संवैधानिक आधार का एक मौलिक पुनर्निर्धारण प्रस्तुत करता है। यह वस्तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) को लागू करने के लिए एक रूपरेखा है। यह केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभाओं को नई शक्तियां प्रदान करता है, और ऐसे संस्थानों का भी निर्माण करता है जो संविधान के संघीय चरित्र को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

3. संशोधन-पूर्व संवैधानिक योजना में भारत के भीतर आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कराधान की दृष्टि थी। उत्पाद शुल्क और उत्पादन पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सातवीं अनुसूची के तहत केंद्रीय संसद की विधायी शक्तियों के दायरे में थे। जिस समय इसे लागू किया गया था, उस समय संविधान में सेवा कर के लिए कोई अलग प्रविष्टि मौजूद नहीं थी।

T.N.Kalyana मंडपम एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2, इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि

एक विषय वस्तु के रूप में सेवा कर संघ की "अवशिष्ट शक्ति" के भीतर था; फिर भी, प्रविष्टि 92 सी को संविधान (88 वां संशोधन) अधिनियम, 2004 द्वारा संघ सूची में शामिल किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि संघ के पास सेवा कर लगाने का विशेष अधिकार था। राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 52 और 54 (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II) द्वारा माल की बिक्री और आवाजाही का कराधान राज्यों के अनन्य दायरे में था। सातवीं अनुसूची की संघ और राज्य सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य की कराधान शक्तियों का परिसीमन सटीक और स्पष्ट था, जिसके लिए बहुत कम गुंजाइश बची।

1 प्रविष्टि 83 और 84, सूची I, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची। 2 2004 पूरक (1) एससीआर 169; (2004) 5 एससीसी 632

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

संघ द्वारा लगाए जा सकने वाले करों और राज्य द्वारा लगाए जा सकने वाले करों में से कोई भी एक दूसरे पर लागू होता है। "समवर्ती सूची" (या सातवीं अनुसूची की सूची III) में कोई कर प्रविष्टि नहीं थी, जो दर्शाती है कि कराधान के लिए संवैधानिक योजना केंद्र और राज्यों के लिए कराधान के दो अलग, विशेष क्षेत्रों को विभाजित करना था।

4. जी. एस. टी. लागू करने का प्रारंभिक कदम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन रिपोर्ट के माध्यम से था और जी. एस. टी. में परिवर्तन के लिए पहली आधिकारिक घोषणा भारत सरकार द्वारा तत्कालीन वित्त मंत्री के बजट भाषण द्वारा आई. डी. 2 में की गई थी; इसे आई. डी. 1 के बजट भाषण में दोहराया गया था और आई. डी. 3 में इसका पालन किया गया था जब उस वर्ष के बजट में कुछ नीतिगत परिवर्तनों की घोषणा की गई थी। नवंबर 2009 में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जारी "भारत में वस्तु और सेवा कर पर पहला चर्चा पत्र" पहला आधिकारिक दस्तावेज था जिसमें प्रस्तावित सुधार की रूपरेखा और जी. एस. टी. मॉडल की बारीकियों को सार्वजनिक रूप से चित्रित किया गया था।

5. वास्तव में, प्रथम चर्चा पत्र में जी. एस. टी. लागू करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के औचित्य की व्याख्या की गई थी। इसने नोट किया कि केंद्र को उत्पादन चरण तक सेवाओं और वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार है, जबकि राज्यों के पास वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने की शक्ति नहीं है जबकि केंद्र के पास बिक्री पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। इसने एक संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया जिसमें जीएसटी की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना के लिए एक तंत्र शामिल होगा जो संघीय ताने-बाने को प्रभावित नहीं करेगा।

6. फिर, केंद्र और राज्यों के बीच विचार-विमर्श के साथ, अधिकार प्राप्त समिति की सहायता से, जी. एस. टी. की शुरुआत करने के लिए संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप "संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011" उस असफल प्रयास के बाद, 2014 का

संशोधन विधेयक अपनाया गया और 8 सितंबर 2016 को पारित किया गया। यह विधेयक "संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016" बन गया।

7. जी. एस. टी. परिषद का गठन सितंबर 2016 में किया गया था। यह एक संवैधानिक संस्थान है जिसमें केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों सहित राज्यों के वित्त मंत्री और विधानसभाओं के सदस्य शामिल हैं।

इसके पास तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. का अधिकार है। एम/एस तिरुमाला

151

निर्माण [एस. रवींद्र भाट, जे.]

“जी. एस. टी. के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र और राज्यों को सिफारिश करना, जिसमें मॉडल जी. एस. टी. कानून, आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के सिद्धांत, कर लगाना, जी. एस. टी. की रूपरेखा, विवाद निपटान, राज्यों की एक विशेष श्रेणी के लिए विशेष प्रावधान आदि शामिल हैं।

जीएसटी परिषद की सिफारिशों ने संसद को कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। 38. जी. एस. टी. व्यवस्था के लागू होने और संशोधन का पारित होना एक दुर्लभ सर्वसम्मति, राजनीतिक स्पेक्ट्रम में एक संकल्प को दर्शाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक एकल अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था है। संशोधन का प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं पर सभी राज्य और संघ करों को शामिल करना है। संघ और राज्यों दोनों के पास वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने की शक्ति होगी। 101 वां संशोधन अधिनियम न तो संघ की और न ही राज्यों की कर लगाने की शक्ति को छीनता है, बल्कि उन्हें क्रमशः वस्तुओं की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 246-ए के माध्यम से संशोधन बनाता है:

क. एक नया विधायी निकाय,

ख. सातवीं अनुसूची की तीन सूचियों के बाहर विधायी प्राधिकरण;

ग. संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को एक ही विषय पर और एक ही समय में विधान बनाने की समवर्ती शक्तियाँ।

9. परिणामस्वरूप संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 द्वारा किए गए विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों की विशिष्टता के अंतर्निहित सिद्धांत से हटकर संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की योजना में एक मौलिक परिवर्तन हुआ है।

10. इसका उदाहरण देने के लिए: जबकि अनुच्छेद 246-ए शक्तियों के विधायी वितरण को बदल देता है, हालाँकि, यह दोनों के बीच संतुलन को खराब नहीं करता है।

3 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017: यह एक राज्य के भीतर सभी आपूर्ति में वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर लगाता है; एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017: यह वस्तुओं

और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाता है; और (3) केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017: यह वस्तुओं और सेवाओं की राज्य के भीतर आपूर्ति पर कर लगाता है।

4 गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2005) 1 एस. सी. आर. 732,152

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

संघ और राज्य। इसके बजाय, यह क्रॉस-सशक्तिकरण का कार्य करता है। एक ओर, यह संघ को उन कुछ विषयों पर विधायी बनाने और कर एकत्र करने में सक्षम बनाता है जो अब तक राज्यों के अनन्य दायरे में थे (जैसे वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर, आदि), जबकि उसके पास अब तक के विधायी अधिकारों (जैसे निर्माण पर कर, सेवाओं पर कर, आदि) को बनाए रखते हुए, सिवाय इसके कि ये कर एक बड़े विधायी निकाय यानी जी. एस. टी. में शामिल किए जाते हैं और इसके तहत लगाए जाते हैं। दूसरी ओर, अनुच्छेद 246-ए उन विषयों को अपने दायरे में लाने के लिए राज्यों की विधायी पहुंच का भी विस्तार करता है जो अब तक उनकी क्षमता से परे थे—जैसे कि सेवाओं की आपूर्ति पर कर, आदि। जैसा कि संघ के मामले में, राज्य भी अपने पास अब तक के विधायी वित्तों (जैसे बिक्री और खरीद पर कर, सट्टेबाजी और जुआ पर कर और विज्ञापनों पर कर) पर करों को लागू करना और लागू करना जारी रखते हैं, हालांकि जीएसटी के एक हिस्से के रूप में जो इन विधायी वित्तों को समाहित करता है।

11. अनुच्छेद 279-ए वस्तु और सेवा कर परिषद (इसके बाद "जी. एस. टी. परिषद") के लिए प्रावधान करता है। यह प्रावधान अंतर्निहित संवैधानिक दर्शन को भी कुछ हद तक बदल देता है। अनुच्छेद 279-ए का उपखंड (1) एक नई संवैधानिक संस्था का निर्माण करता है; (2) उसे संघ और राज्यों को सिफारिशें करने की शक्ति प्रदान करता है; (3) यह प्रावधान करता है कि अन्य संवैधानिक संस्थानों के कुछ कार्य जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर किए जाएंगे।⁶ वास्तव में, जी. एस. टी. परिषद को मॉडल विधानों और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर कर की दरों पर भी सिफारिश करने का अधिकार है।

12. संशोधन अधिनियम के प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

उपरोक्त संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 2 के संदर्भ में, अनुच्छेद 246 के बाद, एक नया अनुच्छेद 246-ए जोड़ा गया जो निम्नानुसार है:

5 उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 246-ए स्पष्टीकरण, अनुच्छेद 269-ए (1), भारत का संविधान देखें।⁶ अनुच्छेद 279-ए, एक विस्तृत चर्चा के लिए।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 154 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

“246 अ. माल और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान-(1) अनुच्छेद 246 और 254 में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (2) के अधीन, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

(2) संसद के पास माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है जहां माल, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।

स्पष्टीकरण।---अनुच्छेद 279 ए के खंड (5) में निर्दिष्ट वस्तु और सेवा कर के संबंध में इस अनुच्छेद के प्रावधान वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होते हैं।”

धारा 7 द्वारा अनुच्छेद 268-ए को हटा दिया गया था। अनुच्छेद 269 के बाद, अनुच्छेद 269-ए जोड़ा गया है, जो इस प्रकार है:

“269 अ. अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का संग्रह -

(1) अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाएगा और ऐसा कर संघ और राज्यों के बीच उसी तरीके से विभाजित किया जाएगा जो वस्तु और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा कानून द्वारा प्रदान किया जाए।

स्पष्टीकरण-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत के राज्य क्षेत्र में आयात के क्रम में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम में वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति माना जाएगा।

(2) खंड (1) के तहत किसी राज्य को बांटी गई राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी।

(3) जहां खंड (1) के तहत लगाए गए कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग अनुच्छेद 246 ए के तहत किसी राज्य द्वारा लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है, वहां ऐसी राशि भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी।

(4) जहां अनुच्छेद 246 ए के तहत किसी राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र की गई राशि का उपयोग खंड (1) के तहत लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है, वहां ऐसी राशि राज्य की समेकित निधि का हिस्सा नहीं होगी।

(5) संसद, कानून द्वारा, आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को तैयार कर सकती है, और जब वस्तुओं, या सेवाओं, या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।”

संशोधन की धारा 12 में अनुच्छेद 279-ए जोड़ा गया, जो इस प्रकार है:

“279 अ. वस्तु एवं सेवा कर परिषद-- -

(1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारंभ की तारीख से साठ दिनों के भीतर, आदेश द्वारा एक परिषद का गठन करेगा जिसे वस्तु और सेवा कर परिषद कहा जाएगा।

(2) वस्तु एवं सेवा कर परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) संघ वित्त Minister.Chairperson;

(ख) राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री। सदस्य;

(ग) वित्त या कराधान का प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री।

(3) खंड (2) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्य, जितनी जल्दी हो सके, अपने बीच से किसी एक को ऐसी अवधि के लिए परिषद का उपाध्यक्ष चुनेंगे जो वे तय करें।

(4) वस्तु एवं सेवा कर परिषद संघ और राज्य को निम्नलिखित पर सिफारिशें करेगी -

(क) संघ, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार जिन्हें वस्तु और सेवा कर में शामिल किया जा सकता है; (ख) वे वस्तु और सेवाएँ जिन्हें वस्तु और सेवा कर के अधीन या उससे छूट दी जा सकती हैं;

(ग) मॉडल वस्तु एवं सेवा कर कानून, अनुच्छेद 269-क के तहत अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए वस्तु एवं सेवा कर का विभाजन और आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शन [एस. रवींद्र भाट, जे.] 156 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

(घ) कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को वस्तु और सेवा कर से छूट दी जा सकती है;

(ई) माल और सेवा कर के बैंड के साथ विभिन्न दरों सहित दरें; (च) किसी प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए किसी विशिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरें;

(छ) अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान; और (छ) वस्तु और सेवा कर से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसा कि परिषद तय करे।

(5) वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस दिन पेट्रोलियम कच्चे तेल, तेज गति वाले डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा।

(6) इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, वस्तु और सेवा कर परिषद को वस्तु और सेवा कर की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए निर्देशित किया जाएगा।

(7) वस्तु एवं सेवा कर परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का आधा हिस्सा इसकी बैठकों में गणपूर्ति का गठन करेगा।

(8) वस्तु एवं सेवा कर परिषद अपने कार्यों के निष्पादन में प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(9) वस्तु एवं सेवा कर परिषद का प्रत्येक निर्णय एक बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई के बहुमत से निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार लिया जाएगा, अर्थात्:---

(क) केंद्र सरकार के मत का भार कुल डाले गए मतों का एक तिहाई होगा, और

(ख) एक साथ लिए गए सभी राज्य सरकारों के मतों का उस बैठक में डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई महत्व होगा।

(10) वस्तु एवं सेवा कर परिषद का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होगी -

((क) परिषद् के गठन में कोई रिक्तता या कोई दोष; या (ख) परिषद् के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या

(ग) परिषद की कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

(11) वस्तु एवं सेवा कर परिषद किसी भी विवाद पर निर्णय लेने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगी -

(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या (ख) भारत सरकार और एक तरफ के किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या

(ग) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच,

परिषद की सिफारिशों या उनके कार्यान्वयन से उत्पन्न होना।”

13. (संशोधन की) धारा 14 में अनुच्छेद 366 (12 ए), (26-ए) और (26-बी) को लागू करने का प्रभाव था। संविधान की सातवीं अनुसूची में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। प्रविष्टि 84 के लिए सूची I (संघ सूची) में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया गया था:

“84. भारत में निर्मित या उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अर्थात्:---

(क) पेट्रोलियम कच्चा;

(बी) उच्च गति डीजल;

(ग) मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है); (घ) प्राकृतिक गैस;

(ई) विमानन टरबाइन ईंधन; और

(च) तंबाकू और तंबाकू उत्पाद।”;

प्रविष्टियाँ 92 और 92 सी (संघ सूची) को हटा दिया गया था। इसी तरह, प्रविष्टि 52 को हटा दिया गया और प्रविष्टि 54 को प्रतिस्थापित किया गया। नई प्रविष्टि 54 इस प्रकार है:

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 158

157

“54. मानव उपभोग के लिए पेट्रोलियम कच्चे, उच्च गति वाले डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन और मादक शराब की बिक्री पर कर, लेकिन अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री या ऐसी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है।”

धारा 19 इस प्रकार है:

“19. इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले किसी भी राज्य में माल या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित किसी भी कानून का कोई प्रावधान, जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के प्रावधानों से असंगत है, किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तब तक लागू रहेगा।”

धारा 20 इस प्रकार है:

“20. (1) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई अड़चन उत्पन्न होती है (संविधान के प्रावधानों से संक्रमण के संबंध में कोई अड़चन भी शामिल है जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के प्रावधानों में राष्ट्रपति की सहमति की तारीख से तुरंत पहले थी), तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकता है, जिसमें इस अधिनियम या कानून द्वारा संशोधित संविधान के किसी भी प्रावधान का कोई अनुकूलन या

संशोधन शामिल है, जो राष्ट्रपति को इस अड़चन को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश ऐसी सहमति की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, इसे बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।”

II. तथ्य।

14. इस मामले में अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाओं से उत्पन्न होने वाली अपीलों के तीन बैच हैं। एक जत्था तेलंगाना राज्य से संबंधित है। उस राज्य के संबंध में तथ्य यह है कि स्थानीय वैट अधिनियम में संशोधन किया गया था-संशोधन पेश किए जाने के बाद। वैट संशोधन एक अध्यादेश के माध्यम से किया गया था, और इसे 13 दिन पहले 17.06.2017 पर लागू किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

101 वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदत्त समय, अर्थात् एक वर्ष। यह संशोधन 16.09.2016 पर लागू हुआ। अध्यादेश में सीमा की अवधि बढ़ाने की मांग की गई और मूल्यांकन को फिर से खोलने की अनुमति दी गई। यह अध्यादेश तब तक जारी रहा जब तक कि राज्य विधानमंडल ने इसे लागू नहीं किया। राज्यपाल ने तब कानून को मंजूरी दी, और यह 02.12.2017 पर लागू हुआ। स्थानीय वैट अधिनियम में संशोधन को चुनौती देते हुए कई व्यापारियों और वैट दाताओं ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और विभिन्न मामलों में इसे खारिज कर दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि राज्य के पास अपने वैट अधिनियम में संशोधन करने की सीमित गुंजाइश थी, जो संशोधन की धारा 19 के संदर्भ में इसे केवल संशोधित संविधान के अनुरूप लाने के लिए किया जा सकता था। अन्य कारणों में यह भी शामिल था कि अध्यादेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 01.07.2017 के बाद राज्य को विधायी क्षमता से वंचित कर दिया गया था।

15. बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न अपीलों के समूह में, पक्षकार इस तथ्य से व्यथित थे कि महाराष्ट्र वैट संशोधन अधिनियम, जिसे शुरू में 15.04.2017 पर बनाया गया था, को बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले द्वारा पढ़ा गया था। उस स्थिति को एक संशोधन के माध्यम से उलटने की मांग की गई थी, जिसे 15.04.2017 पर लागू किया गया था और बाद में पूर्वव्यापी प्रभाव को देखते हुए निर्णय के प्रभाव को उलटने के लिए एक प्रभाव में लाया गया था। ऐसे पीड़ित पक्षों के नेतृत्व में दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। नतीजतन, वे अपील में हैं।

16. गुजरात के मामलों के समूह में, गुजरात मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (इसके बाद "गुजरात वैट अधिनियम" के रूप में

संदर्भित) में धारा 84 ए पेश की गई थी, जिसे 06.04.2018 पर राजपत्रित किया गया था, लेकिन 1.4.2006 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि यदि "कुछ अन्य कार्यवाहियों" में किसी विशेष मुद्दे के लिए एक निचला मंच कोई निर्णय देता है जो राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है और ऐसे निर्णय के खिलाफ अपील उच्च मंच के समक्ष लंबित है तो संशोधन के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय इस तरह के मुकदमे में खर्च की गई अवधि को बाहर रखा जाएगा। पूर्वव्यापी प्रभाव वाला ऐसा प्रावधान देकर राज्य विधानमंडल ने इस प्रकार उन आकलनों को फिर से खोलने में सक्षम बनाने की कोशिश की जो पहले ही वास्तविकता प्राप्त कर चुके थे। गुजरात उच्च न्यायालय ने 01.07.2017 के बाद विधायिका की ओर से विधायी क्षमता की कमी के आधार पर संशोधन को खारिज कर दिया, और यह भी कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना था।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 160

159

III. अपीलार्थी-राज्यों के तर्क

17. तेलंगाना राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दातार, महाराष्ट्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) श्री बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि संविधान संशोधन 16.09.2016 पर पेश किया गया था। यह रेखांकित किया गया कि इसके प्रावधानों द्वारा दोनों विधानसभाओं की शक्तियों को सीमित करने के लिए राज्य और संघ सूची में विभिन्न प्रविष्टियों में भारी संशोधन किया गया था। संशोधन का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान की शक्तियों को फिर से व्यवस्थित करना था जिसकी कल्पना मूल संविधान निर्माताओं ने की थी। अप्रत्यक्ष कर: विशेष रूप से, बिक्री कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर इस संशोधन के विषय थे। संविधान के मूल इरादे और सीमा शुल्क लगाने के संबंध में शक्तियों को बरकरार रखा गया था। पहली बार, संशोधनों ने राज्यों और संसद को विशेष रूप से कानून बनाने से वंचित कर दिया और मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के संबंध में साझा या एकत्रित संप्रभु शक्तियों की अवधारणा को पेश किया। इन्हें एक समग्र शब्द "वस्तु और सेवा कर" में लाया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि कराधान के इस क्षेत्र के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था। पहली बार, कराधान की शक्ति का पता संविधान के एक ठोस प्रावधान से लगाया जा सकता है, जिसे संशोधन द्वारा पेश किया गया था। इसके अलावा, कराधान के एकत्रित शुल्क के सिद्धांत विभाजन का मुद्दा एक नई इकाई, वस्तु और सेवा कर परिषद (इसके बाद "जी. एस. टी. परिषद") पर छोड़ दिया गया, जिसे एक संवैधानिक इकाई के रूप में बनाया गया था। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि सत्ता का संघीय संतुलन बना रहे और वास्तव में इसे आगे बढ़ाया जाए।

18. विद्वान वकील ने इस बात पर जोर देने के लिए संशोधन के प्रावधानों पर भरोसा किया कि जी. एस. टी. परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं और निर्णय लेने में केंद्र का केवल एक तिहाई महत्व है। शेष राशि सामूहिक रूप से राज्यों के पास है। इसके अलावा, परिषद में कोई भी निर्णय प्रभावी हो जाता है जब इसे 3/4 वें बहुमत से वोट दिया जाता है। 19. यह तर्क दिया गया था कि अप्रत्यक्ष कराधान शक्ति के पुनर्वितरण और संशोधन के माध्यम से इसे प्रभावी प्रभाव देने से लाए

गए लगभग क्रांतिकारी परिवर्तन का मतलब था कि संसदीय और राज्य दोनों विधायी शक्तियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर और अन्य करों के संबंध में अस्वीकार कर दिया गया था जो राज्य अब तक लगा सकते थे और एकत्र कर सकते थे। संशोधन के प्रभावी अधिनियम के रूप में, सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची I) की प्रविष्टियों 84 में कराधान के अन्य प्रावधान -

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

भारत के संविधान और राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 54 और 62 में भी संशोधन किया गया। कराधान के इन पहलुओं के सुधार के परिणामस्वरूप ऐसी शक्तियों को राज्य और केंद्र द्वारा साझा की गई संप्रभु कराधान शक्ति के रूप में एकत्र या एकत्र किया गया। यह एक अलग प्रविष्टि का विषय बन गया, अर्थात् अनुच्छेद 246 ए। अनुच्छेद 246 ए एक गैर-अस्थायी खंड के साथ शुरू होता है और अनुच्छेद 246 को ओवरराइड करता है जो सूची 1 और 2 के संदर्भ में संघ और राज्यों के साथ विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, और अनुच्छेद 254 जो समवर्ती सूची की विषय वस्तु से संबंधित है, यानी सूची III और राज्यों और संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बीच किसी भी टकराव (प्रतिकूलता के संदर्भ में) के समाधान से संबंधित है। 20. अनुच्छेद 246 ए का प्रभाव यह है कि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाई गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246 ए (2) में कहा गया है कि संसद के पास अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और दोनों के संबंध में कानून बनाने की प्रबल शक्ति है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 269 ए है जो संघ को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर जी. एस. टी. एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है।

संघ और राज्य जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों पर संसद द्वारा प्रदान किए जाने वाले तरीके से। के अन्य प्रावधान

अनुच्छेद 269 ए उन संग्रहों की प्रकृति को स्पष्ट करता है जो भारत की समेकित निधि नहीं हैं। अनुच्छेद 279 ए जी. एस. टी. परिषद के लिए प्रावधान करता है और संतुलित निर्णय लेने, संघ और राज्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसकी संरचना से विस्तृत रूप से संबंधित है।

21. यह भी प्रस्तुत किया गया कि इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 366 [12 (ए)] पेश किया गया था, जो वस्तु एवं सेवा कर (जी. एस. टी.) की अवहेलना करता है और वस्तुओं की आपूर्ति पर कर लगाता है।

और सेवाएँ या दोनों, मानव उपभोग के लिए मादक शराब को छोड़कर

राज्यों की ओर से यह आग्रह किया गया कि संशोधन के लागू होने के साथ, संसद और राज्यों ने महसूस किया कि कानून में कोई भी बदलाव या मौजूदा कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग असंभव

हो जाएगा। परिणामस्वरूप, इन संभावनाओं को पूरा करने के लिए, कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए थे, अर्थात् धारा 19 जिसमें पहले यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी राज्य में तुरंत लागू वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित कानून।

संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले तब तक लागू रहेगा जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 162

सक्षम प्राधिकारी।” दूसरी संभावना यह थी कि ऐसे संशोधनों के साथ या उनके बिना ऐसे कानून संशोधन के प्रारंभ से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होने थे। धारा 20 राष्ट्रपति को आदेश द्वारा प्रावधान करने के लिए अधिकृत करती है, जिसमें संशोधन और "किसी भी" को अपनाना शामिल है।

किसी भी दोष के मामले में संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान का प्रावधान, जिसमें राज्य के प्रावधानों से संक्रमण के संबंध में दोष भी शामिल है, जैसा कि वे संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले थे, तीन साल की अवधि के लिए।”

22. संशोधन की धारा 19 को ध्यान में रखते हुए, तेलंगाना विधानमंडल ने मौजूदा राज्य कानून-मूल्य वर्धित कर अधिनियम (इसके बाद "तेलंगाना वैट अधिनियम") में संशोधन किया। 7. संशोधित प्रावधानों ने निर्धारण कार्यालय को उन विवरणियों का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार दिया, जिनका पहले मूल्यांकन किया गया था-अतिरिक्त रूप से दो साल की अवधि के लिए। दूसरे शब्दों में, मूल रूप से पुनर्मूल्यांकन की शक्ति चार साल तक सीमित थी। अवधि को दो और वर्षों तक बढ़ाने का मतलब था कि जिन डीलरों के आकलन या तो नोटिस से बच गए थे और जिन्होंने गलत घोषणा की थी या जानकारी को रोक दिया था, वे अब दो साल की और अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन की संभावना के संपर्क में आ सकते हैं।

23. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह संशोधन तेलंगाना के राज्यपाल द्वारा 17.06.2017 पर जारी एक अध्यादेश के माध्यम से किया गया था। राज्य वैट अधिनियम का 30.06.2017 पर कोई प्रभाव समाप्त होना था। हालाँकि, इससे पहले, इसके प्रावधानों को अध्यादेश के माध्यम से संशोधित किया गया था जिसे बाद में राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के माध्यम से कानून में बदल दिया गया और 02.12.2017 पर लागू किया गया। तेलंगाना जी. एस. टी. अधिनियम 30.06.2017 से पहले लागू किया गया था। इसने मौजूदा कानून, यानी राज्य वैट अधिनियम को निरस्त कर दिया, लेकिन धारा 174 के आधार पर, राज्य वैट अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों को जारी रखा गया और सभी लंबित कार्यवाही जहां तक वे चल रही मूल्यांकन कार्यवाही और उन मामलों से संबंधित हैं जो शून्य नहीं हुए थे।

24. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तेलंगाना और गुजरात उच्च न्यायालयों के विवादित निर्णय गलत हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की व्याख्या कि "संशोधन" अभिव्यक्ति का सीमित महत्व है, आधारहीन है। विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

इस न्यायालय के कई निर्णयों, विशेष रूप से ए. के. रॉय बनाम यू. ओ. आई. 8 (इसके बाद, "ए. के. रॉय") और कृष्णा में सात न्यायाधीशों के निर्णय के संदर्भ में अध्यादेश।

कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 9 (इसके बाद, "कृष्ण कुमार सिंह")

घोषणा की कि किसी अध्यादेश के प्रभाव और राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के प्रभाव के बीच कोई अंतर नहीं है। अप्रत्याशित घटनाओं को पूरा करने के लिए विशेष शक्ति की प्रकृति में होने के कारण, कार्यपालिका को अनुच्छेद 214 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सीमित अवधि के लिए कानून बनाने का अधिकार था। इसी तरह संघ की कार्यपालिका को अनुच्छेद 123 द्वारा अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था।

25. विद्वान वकील ने भी इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया

रामकृष्ण रामनाथ बनाम जनपद सभा 10 (इसके बाद, "रामकृष्ण"

रामनाथ) और इस सिद्धांत पर भरोसा किया कि जब तक संशोधन करने की शक्ति मौजूद है, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को उस शक्ति के प्रयोग में सीमित नहीं किया जा सकता है जो पूर्ण और संप्रभु थी। तेलंगाना और गुजरात उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई व्याख्या कि संशोधन अभिव्यक्ति ने केवल एक सीमित शक्ति प्रदान की है जो संविधान के संशोधनों के अनुरूप मौजूदा अधिनियमों को लाने के लिए है, गलत थी। वास्तव में, यह धारा 19 के माध्यम से व्यक्त की गई बचत और राष्ट्रपति की शक्ति के उद्देश्य और विस्तार को-बिना किसी चेतावनी के-अनुचित रूप से सीमित करने के बराबर था।

26. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि किसी अध्यादेश का प्रभाव और कानून का प्रभाव समान है जो यह है कि वे स्थान या विषय वस्तु को उस हद तक बांधते हैं जब तक वे इसके लिए प्रदान करते हैं, तो अंतर केवल उनके निर्माण के तरीके में निहित है। विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि अंतर कानून की सामग्री या प्रभाव के बजाय अपनाई गई प्रक्रिया में निहित है। जबकि एक अध्यादेश की उत्पत्ति एक अलग इकाई के माध्यम से होती है जो कार्यपालिका (सीमित विधायी शक्ति के साथ) है, दूसरी ओर, अधिनियम एक राज्य विधायी या संसद की अभिव्यक्ति है। यह भेद कानून के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकता है जो समान है और उन पक्षों को बाध्य करना जारी रखेगा जिनके लिए स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

8 (1982) 2 एस. सी. आर. 272 9 (2017) 5 एस. सी. आर. 160

10 1962 पूरक।(3) एससीआर 70 163

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 164

27. इस प्रस्ताव के समर्थन में कि राज्य की विधायी शक्ति और कार्यपालिका के बीच कोई अंतर नहीं है, विद्वान वकील ने आर. के. गर्ग बनाम भारत संघ 11 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। यह आगे तर्क दिया गया कि अध्यादेश को सदन, या तो राज्य विधानमंडल या संसद के समक्ष रखने या पेश करने की आवश्यकता वाला प्रावधान एक अधिनियमित कानून को पेश करने के अभ्यास से पूरी तरह से अलग था। पहला स्वयं विधायी गतिविधि का एक हिस्सा था। यदि विधायिका, अर्थात् राज्य विधायिका या संसद अपनी शर्तों में अध्यादेश को मंजूरी देती है, तो यह एक संसदीय या राज्य अधिनियम बन जाता है। विद्वान वकील ने इस मुद्दे या बिंदु पर जोर दिया कि अध्यादेश की शर्तों का एक अलग अवतार अनिवार्य रूप से संविधान के तहत एक आवश्यकता नहीं है। अध्यादेश के केवल अनुमोदन के परिणामस्वरूप राज्य विधानमंडल द्वारा इसे अधिनियमित और स्वीकार किया जाता है जो बदले में उसके द्वारा अधिनियमित कानून के निकाय के माध्यम से अध्यादेश की शर्तों को आत्मसात करता है। दूसरे शब्दों में, यदि राज्य विधानमंडल या संसद अध्यादेश को अस्वीकार करती है या अध्यादेश के किसी भी हिस्से को मंजूरी नहीं देती है और अध्यादेश को एक अधिनियम के रूप में मूर्त रूप देती है, तो वह अधिनियम उस तारीख से निर्णायक होगा जब अध्यादेश को लागू किया गया था। हालाँकि, अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति के संदर्भ में, अध्यादेश का सीमित जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा तेलंगाना में अध्यादेश की शर्तों को मंजूरी देने और दूसरे संशोधन के संदर्भ में इसे शामिल करने पर, जो 02.12.2017 पर लागू किया गया था, इसकी शर्तें वापस संबंधित थीं। इसलिए, कानून बनाने की राज्य की शक्ति को निरंतरता में देखा जाना चाहिए या इसे लागू होने की तारीख से जारी रखा जाना चाहिए जो 17.06.2017 है और राज्य अधिनियम से बना है। परिणामस्वरूप, राज्य की ओर से कानून बनाने की शक्ति भी बरकरार रखी गई। विद्वान वकील ने प्रस्तुत करने के समर्थन में फ्यूस्ट डे लॉसन लिमिटेड बनाम जिंदल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 12 में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। महाराष्ट्र वैट अधिनियम के मामले में, यह रेखांकित किया गया कि संशोधन अधिनियम 15.04.2017 पर लागू किया गया था। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम (इसके बाद "सी. जी. एस. टी. अधिनियम") 01.07.2017 पर लागू हुआ। राज्य वैट अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में, 10 प्रतिशत की पूर्व जमा राशि अपील की सुनवाई के लिए शर्त बन गई।

11 (1982) 1 एससीआर 947 12 2001 (3) एससीआर 479

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

28. महाराष्ट्र राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि जो सामग्री है वह कानून बनाने की शक्ति का अस्तित्व है न कि उस शक्ति के प्रयोग का तरीका। इसलिए, कानून बनाने की शक्ति का अस्तित्व धारा 19 द्वारा संरक्षित किया गया था; इसका उद्देश्य मौजूदा कानूनों के दोनों भागों को संरक्षित करना और राज्य विधानमंडल और संसद को मौजूदा कानून में संशोधन या निरसन करने की

अनुमति देना भी था।संवैधानिक संशोधन होने के कारण, किसी भी अभिव्यक्ति या शब्द की व्याख्या सीमित तरीके से नहीं की जानी चाहिए।तेलंगाना और गुजरात उच्च न्यायालयों का यह तर्क कि संशोधन की शक्ति मौजूदा अधिनियमों, यानी 101 वें संशोधन की स्पष्ट शर्तों के अनुरूप राज्य वैट अधिनियमों को लाने तक सीमित थी, गलत था।यह प्रस्तुत किया गया था कि 101 वें संशोधन में निर्दिष्ट तिथि, यानी एक वर्ष की समाप्ति, जो प्रभावी रूप से 30 जून, 2017 थी, तक सक्षम विधानसभाओं, यानी राज्य और संघ की शक्तियों को सीमित नहीं किया गया था।विद्वान वकील ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में किए गए संशोधनों की ओर भी इशारा किया, जो तेलंगाना और गुजरात संशोधनों के मामले में किए गए संशोधनों की तरह ही थे, जिन्होंने कुछ मामलों में सीमा की अवधि को बढ़ाया था।यह तर्क देना गलत है कि राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति से वंचित किया गया था।राज्य सूची 54 और 62 में प्रासंगिक प्रविष्टियों में परिवर्तन किए जाने के बावजूद संविधान के संशोधित प्रावधानों के लिए शक्ति का पता लगाया जा सकता था।यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया था

और यू. ओ. आई. और ए. एन. आर. वी. में चर्चा की गई।मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड 13.

29. यह आग्रह किया जाता है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद की एक घटक शक्ति है।अनुच्छेद 368 (2) के तहत, संविधान में संशोधन एक विधेयक पेश करके शुरू किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को मंजूरी देने के बाद, संविधान में विधेयक की शर्तों के अनुसार संशोधन किया जाता है।दूसरे शब्दों में, संविधान संशोधन विधेयक का प्रत्येक प्रावधान संशोधित संविधान का हिस्सा बन जाता है।

30. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान में धारा 19 को विशिष्ट रूप से शामिल न करने से कोई अंतर नहीं पड़ता है।यह अभी भी संशोधित संविधान का एक हिस्सा है।इस संबंध में सातवें संवैधानिक संशोधन का उल्लेख किया गया है जिसने राष्ट्रपति को भाग डी राज्यों के प्रशासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की थी।उक्त संशोधन के बाद,

13 2022 (9) एससीआर 300 165

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 166 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

विनियमों को सीमित अवधि के लिए जारी रखा गया था।संवैधानिक संशोधन पूरी तरह से संविधान का हिस्सा बन गया।ए. के. रॉय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया है।

31. महाराष्ट्र राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया कि महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 की धारा 26 में संशोधन (इसके बाद "एम. वी. ए. टी. अधिनियम" के रूप में) जिसमें पूर्व-जमा की आवश्यकता होती है, संशोधन के साथ असंगत नहीं है।यह प्रक्रियात्मक प्रकृति का है और निर्धारिती का कोई निहित अधिकार नहीं लिया गया था।यह भी विवाद में नहीं है कि यह 1 जुलाई,

2017 से जी. एस. टी. की शुरुआत से पहले के पिछले शुल्कों के संबंध में है और इसलिए, अन्यथा भी महाराष्ट्र जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 174 द्वारा सहेजा जाता है।

32. यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 26 (6 ए) और 26 (6 बी) की सरल भाषा स्पष्ट करती है कि यह उन सभी मामलों में लागू होती है जहां आदेश 15 अप्रैल, 2017 के बाद पारित किया जाता है और एक अपील को प्राथमिकता दी जाती है। उस प्रावधान के लिए केवल 10 प्रतिशत की पूर्व जमा राशि की आवश्यकता होती है और यह अपीलीय प्राधिकरण/न्यायाधिकरण के विवेक को छीन लेता है। यह अपील के वैधानिक अधिकार को नहीं छीनता है और केवल न्यायाधिकरण के विवेकाधिकार को हटाकर इसे नियंत्रित करता है। पूर्व-जमा की शर्त भी इसे मनमाना बनाने के लिए एक कठिन शर्त नहीं है। इसलिए, एकमात्र सवाल यह है कि क्या पूर्व-जमा के बिना अपील करने का कोई निहित अधिकार है। संशोधन की सरल भाषा ने 15 अप्रैल, 2017 के बाद मूल प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने के मामले में अपील प्राधिकरण के विवेकाधिकार को छीन लिया है न कि अपील के अधिकार को। राज्य निर्णयों पर निर्भर करता है, यह कहने के लिए कि अपील करने का अधिकार अपरिवर्तित रहता है, केवल इसकी शर्तों को नियंत्रित किया जाता है, या विनियमित किया जाता है, पूर्व-जमा आवश्यकताओं के साथ, अपीलीय स्तर पर, अर्थात् अनंत

मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य 14; विजय प्रकाश डी. मेहता बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (निवारक), बॉम्बे 15 हरियाणा राज्य बनाम मारुति उद्योग लिमिटेड और अन्य 16 तिरुमाली केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 17; नीना अनेजा और अन्न। वी. जय प्रकाश एसोसिएटेड लिमिटेड 18.

33. गुजरात राज्य का आग्रह है कि उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार नहीं किया कि कुछ इसी तरह की स्थितियों में, यह अदालत ए. हाजी में

14 (1975) 3 एससीआर 220

15 (1988) सप्लीमेंट (2) एससीआर 434 16 (2000) सप्लीमेंट 3 एससीआर 185 17 (2011) 4 एससीआर 739 18 (2021) 15 एससीआर 96

अब्दुल शकूर एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य 19 (इसके बाद, "हाजी अब्दुल शकूर")

1939 के अधिनियम के तहत आकलनों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने की राज्यों की शक्ति को मान्यता दी, भले ही पहले का अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के अभाव में विफल रहा हो। यह भी बताया गया कि मैसर्स वेस्ट में यह अदालत

रामनाड इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम मद्रास राज्य 20 ने मान्यता दी

जिन अधिनियमों को असंवैधानिक और गैर-कानूनी घोषित किया गया था, उनकी अधिसूचना के तहत की गई कार्रवाइयों को पूर्वव्यापी रूप से मान्य करने की राज्यों की शक्ति। राजस्थान राज्य बनाम मंगीलाल पिंडवाल 21 में इस अदालत के फैसले पर भी भरोसा रखा गया है, जिसमें निरस्त

किए गए प्रावधानों को उस अवधि के लिए संशोधित करने की विधायिका की शक्ति को बरकरार रखा गया है जब ये प्रावधान निरसन की तारीख तक लागू थे। गुजरात जी. एस. टी. अधिनियम की धारा 166 को निरस्त करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वैट अधिनियम को बिल्कुल भी निरस्त नहीं किया गया है और इसलिए, निरसन के परिणाम नहीं हो सकते हैं।

34. यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 84 ए न तो मनमाना है और न ही अनुचित है, बल्कि इसका उद्देश्य कर अधिकारियों को उन डीलरों से कर एकत्र करने की अनुमति देकर इक्विटी और क्षतिपूर्ति करना है, जिन्होंने अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ डाला है, लेकिन इसे सरकारी खजाने में भुगतान नहीं किया है, इस प्रकार एक विशेष बड़े संविधान द्वारा रखे गए धन के अन्यायपूर्ण संवर्धन से बचा जा सकता है।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम. भारत संघ 22 (इसके बाद "मफतलाल")

उद्योग ")। यह आग्रह किया जाता है कि अन्यायपूर्ण संवर्धन की बहाली और रोकथाम किसी भी वैधानिक प्रावधानों के बावजूद लागू समानता का एक सिद्धांत है। इसके अलावा, यह तर्क दिया जाता है कि धारा 84 ए नए कर या देयता को लागू नहीं करती है, बल्कि केवल कर के संग्रह की सुविधा प्रदान करती है जिसका बोझ अंतिम उपभोक्ता पर डाला गया था और यह कि एकत्रित कर, सार्वजनिक धन होने के कारण और इसकी घटना और बोझ को हमेशा अप्रत्यक्ष करों में माना जाता है, कुछ विक्रेताओं को कर के लाभ को बनाए रखने की अनुमति देना सबसे असमान और अनुचित होगा जो पारित किया गया है।

35. इसके बाद यह आग्रह किया गया कि धारा 84 ए एक मान्यकारी अधिनियम है जो समय सीमा को बढ़ाता है जिससे कर विक्रेताओं के हाथों में सार्वजनिक धन का संग्रह संभव हो जाता है। गुजरात राज्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले के बाद पुनरीक्षण नोटिस भेजे गए थे।

19 1964 (8) एससीआर 217; एआईआर 1964 एससी 1729 20 1963 (2) एससीआर 747

21 (1996) सप्लीमेंट (3) एससीआर 98 22 1996 सप्लीमेंट। (10) एससीआर 585 167

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 168

लिमिटेड 23. वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 84 ए के तहत निर्धारित समय सीमा बहुत लंबी नहीं है यदि सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 61 (बी), 62, 63 (बी), 64, 65, 66, 67, 92, 94, 96, 106, 107, 108, 109, 110 और 136 को देखा जाता है जो किसी भी घटना की घटना से 12 या 30 साल की समय सीमा प्रदान करता है जिसमें कई साल भी लग सकते हैं।

IV. प्रत्यर्थी-मूल्यांकनकर्ताओं के तर्क

36. निर्धारिती-प्रत्यर्थियों की ओर से श्री कपिल सिब्बल, श्री एस. गणेश, श्री नानकानी और श्री सोपारकर, विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री सुजीत घोष, अधिवक्ता (इसके बाद "निर्धारिती") ने तर्क

दिया कि असंगत मौजूदा कानून को जारी रखना केवल उन्हें संविधान के संशोधित ढांचे के अनुरूप (संशोधनों के माध्यम से) बनाने के उद्देश्यों के लिए है। यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधन की धारा 19 के तहत शक्तियों के दायरे को स्पष्ट करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 243ZF से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जिसे धारा 19 के समान तरीके से जोड़ा गया है। हालाँकि, उनके बीच दो विशिष्ट विशेषताएं हैं, पहली बात यह है कि धारा 19 के विपरीत अनुच्छेद 243ZF को संविधान के मुख्य भाग में शामिल किया गया था, और दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 243ZF में एक गैर-अबाधित खंड है जो संविधान के भाग IXA में निहित सभी अनुच्छेदों को ओवरराइड करने की मांग करता है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2017 ("CAA") की धारा 19 केवल संशोधन के प्रावधान को ओवरराइड करती है न कि भारत के संविधान को। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद 243 जेडएफ को सी. ए. ए. की तुलना में उच्च स्तर पर कहा जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि इस अदालत ने सुंदरगढ़ में अनुच्छेद 243 जेडएफ की व्याख्या की थी

जिला आदिवासी अधिवक्ता संघ और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य 24

(इसके बाद सुंदरगढ़ जिला "I", जिसमें इस न्यायालय ने पैरा में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

".....स्पष्ट रूप से, एक मौजूदा कानून को जारी रखने का उद्देश्य (भले ही यह भाग IX-A के साथ असंगत हो) इसे भाग IX-A के अनुरूप बनाने के लिए मौजूदा कानून में आवश्यक संशोधन करने में सक्षम बनाना था।

37. यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेडएफ और धारा 19 की भाषा समान सामग्री के करीब है,

23 (2017) 13 एससीआर 25. 24 (2013) 6 एससीआर 420

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

सुंदरगढ़ जिला (ऊपर), यह स्पष्ट है कि धारा 19 के तहत संशोधन करने की शक्ति मौजूदा असंगत विधानों को संशोधन के अनुरूप बनाने तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, इसका उद्देश्य विसंगतियों को ठीक करना और दरारों को दूर करना है। इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुच्छेद 243 जेडएफ के विपरीत, जो संविधान का एक हिस्सा है और संविधान के भाग IXA को भी ओवरराइड करता है, धारा 19 संविधान का हिस्सा नहीं है और संविधान के किसी भी प्रावधान को ओवरराइड नहीं करती है, सी. ए. ए. की धारा 19 के तहत संशोधन करने की शक्ति सुंदरगढ़ जिला (सुप्रा) में व्याख्या किए गए अनुच्छेद 243 जेडएफ के तहत उपलब्ध संशोधन की शक्ति की तुलना में और भी कम होगी। 38. वकील ने आग्रह किया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 143 (2) के रूप में एक समान संक्रमणकालीन प्रावधान पेश किया गया था, जिसमें भाग III की शुरुआत के साथ 'अस्थायी विधान' की अवधारणा पेश की गई थी।

राम कृष्ण रामनाथ (ऊपर) में।

39. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निगमन के माध्यम से लेवी को जारी रखने की व्यक्त शक्ति दी गई थी, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़कर कहा कि ऐसे मामलों में भी, प्रांतीय विधानमंडल की शक्ति बेहद सीमित है और निश्चित रूप से इसका उपयोग 'घटना को बदलने' के लिए नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, लेवी को जारी रखने की ऐसी शक्तियां पूरी तरह से अनुपस्थित हैं और तदनुसार सी. ए. ए. की धारा 19 के तहत शक्तियों को एक अत्यंत संकीर्ण ढांचे में माना जाएगा, यानी संविधान के अनुरूप कानून लाने तक सीमित होगा।

40. यह प्रस्तुत किया गया था कि 'संशोधन' शब्द की व्याख्या शाब्दिक रूप से नहीं की जानी चाहिए, इसके बजाय प्रासंगिक व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए। प्रासंगिक व्याख्या को लागू करने से, यह प्रतीत होता है कि संशोधन अधिनियम की धारा 19 को इस तरह से जोड़ा गया है जो कानून की पुस्तकों से अंतिम निरसन और उन्मूलन पर विचार करता है। इससे पता चलता है कि विधायिका ने संबंधित कानून के जीवन को कम करने पर विचार किया और राज्य संबंधित कानून में और अधिक जीवन देने के लिए संशोधन करने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। इसके अलावा, 'असंगत' शब्द का उपयोग बाद में 'संशोधित होने तक' शब्द के साथ किया गया, स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि इरादा असंगत प्रावधानों को सीमित समय के लिए जीवित रहने देना था, जब तक कि इसे सुसंगत बनाने के लिए संशोधित नहीं किया जाता है। यदि इरादा संशोधन करने के लिए पूर्ण शक्ति प्रदान करने का होता, तो धारा 19 को इस तरह से जोड़ा जाता कि इसमें 'संशोधन के अधीन' का प्रावधान किया जाता, जो तब 169 का सुझाव देता।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 170

कि मौजूदा असंगत कानून 'जैसा है' या 'जैसा संशोधित किया गया है', एक वर्ष के अंत तक या इसके निरसन, जो भी पहले हो, तक लागू रह सकता है। हालांकि, नौसिखियों के मामले में ऐसा नहीं है।

41. इसके अलावा, उद्देश्यपूर्ण निर्माण को लागू करके, सी. ए. ए. की धारा 19

'उपचारात्मक विधायी कार्रवाई' के अभ्यास को स्वीकार करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि

संविधान के अनुच्छेद 279-ए (6) के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर की एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता और वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए संविधान में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था। इस सामंजस्य की व्याख्या की गई है

भारत संघ बनाम वी. के. सी. फुटस्टेप्स इंडिया (पी) लिमिटेड 25 में उच्चतम न्यायालय ने

इसका अर्थ सहकारी संघवाद प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य और केंद्र के बीच विधायी सद्भाव है। इसलिए, केंद्र और राज्य के बीच या राज्यों के बीच सामंजस्य का यह घोषित उद्देश्य तब प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब संशोधन की धारा 19 के तहत संशोधन की शक्ति का उपयोग करते हुए, कोई राज्य मौजूदा कर कानून के संचालन और विस्तार का विस्तार करता है।

42. यह तर्क दिया जाता है कि धारा 19 की व्याख्या विधायी शक्ति प्रदान करने के रूप में करना जो गैर-उपचारात्मक है और पहले की तुलना में इसमें अधिक जीवन सांस लेना है, संवैधानिक नैतिकता के दांतों में होगा और केल्सन द्वारा प्रस्तावित 'कानून के शुद्ध सिद्धांत' के सिद्धांत के विपरीत होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्ण विधान भारत के संविधान से निचले पायदान पर खड़ा है और कभी भी ग्रंडनोर्म के साथ टकराव नहीं कर सकता है। तदनुसार, संशोधन की धारा 19 में जो भी विधायी शक्ति दी गई है, उसे संविधान के अनुच्छेद 245 और 246 के अधीन होना होगा। यदि बाद के दो अनुच्छेदों के तहत, राज्य के पास किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने की कोई शक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे सातवीं अनुसूची की सूची II से हटा दिया गया है या काट दिया गया है, तो संशोधन की धारा 19 को ऐसे संवैधानिक प्रतिबंध को ओवरराइड करने के लिए सेवाओं में नहीं डाला जा सकता है। वकील का आग्रह है कि पूरा संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया का पालन करके अधिनियमित किया गया था। जबकि उक्त अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है, इसलिए संशोधन की धारा 19 को संविधान का हिस्सा नहीं बनाए जाने को अनुच्छेद 368 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित नहीं किया गया माना जा सकता है।

25 2021 (15) एससीआर 169

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

संविधान से। हालाँकि, यह देखते हुए कि संशोधन के शेष प्रावधानों के साथ, संशोधन की धारा 19 भी संशोधन के तहत निर्धारित पूरे अभ्यास से गुजरी, एक संभावित विचार सामने आता है कि संशोधन की धारा 19 शायद संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक सहायक है जो विधानमंडल को उपलब्ध 'आकस्मिक और सहायक' शक्तियों का उपयोग करके अधिनियमित की गई हैं। यह सर्वविदित और सर्वसम्मत है कि आनुषंगिक और सहायक शक्तियों का प्रयोग मुख्य विधान की सहायता के लिए किया जाता है।

आर. अब्दुल कादर बनाम बिक्री कर कार्यालय मामले में यह अदालत 26)। इसलिए, व्याख्या करने के लिए

संशोधन की धारा 19 में "संशोधन" शब्द का अर्थ उपचारात्मक विधान बनाने की तुलना में व्यापक समानांतर शक्ति प्रदान करना है, जो जी. एस. टी. की शुरुआत के माध्यम से एक साथ शुल्क लगाने के संशोधित संवैधानिक ढांचे के विपरीत है, इसे संशोधन के मुख्य विषय की सहायता के लिए नहीं कहा जा सकता है।

43. वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि यह मानते हुए कि धारा 19 को संसद द्वारा सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए (सूची II या सूची III में सूचीबद्ध नहीं किए गए मामलों के लिए एक अवशिष्ट प्रविष्टि होने के नाते, जिसमें सूची II या III में उल्लिखित कोई भी कर शामिल नहीं है), तब भी ऐसे मामलों में, ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल संसद

द्वारा किया जा सकता है और किसी भी तरह से राज्य विधानमंडलों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है जिससे वे पूर्ण विधानों में संशोधन करने में सक्षम हो सकते हैं। न तो अनुच्छेद 258 और न ही संविधान का अनुच्छेद 258 ए संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों को विधायी शक्ति के किसी भी हस्तांतरण को स्वीकार करता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि संसद ने विधायी कार्य राज्य विधानमंडल को सौंपे हैं।⁴⁴ वकील ने तर्क दिया कि वैट कानून में संशोधन अनुच्छेद 246 ए में इसकी शक्ति के स्रोत को भी निर्धारित नहीं कर सकता है। यह दो कारणों से है, पहला, अनुच्छेद 246 ए के तहत, राज्य के साथ-साथ केंद्र द्वारा भी एक साथ शुल्क लगाया जाना चाहिए, जिसका दायरा वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा, अनुच्छेद 246 ए माल और सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति पर विचार करता है, जो एक निश्चित शब्द है, जो पूरी तरह से अलग है और बिक्री पर कर से भी व्यापक है। जी. एस. टी. को किसी भी तरह से बिक्री पर कर के बराबर नहीं माना जा सकता है।

45. यह तर्क दिया जाता है कि धारा 19 में विचार किया गया है कि 'का कोई प्रावधान किसी राज्य में लागू वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर से संबंधित कोई कानून

26 (1964) 6 एससीआर 867 171

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 172

इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले 'में बना रहेगा

बल तब तक जब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है या एक वर्ष की समाप्ति तक जो पहले है। इसलिए, धारा 19 का ई. डी. आई. सी. ई. संशोधन की शुरुआत से पहले यानी 15.09.2016 पर लागू कानून पर आधारित है।

46. एक मामले में, के 31.12.2007 दिनांकित आदेश के अनुसार

श्री रायलसीमा अल्कलीज एंड एलाइड केमिकल्स लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 27 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, के तहत प्रवेश कर का उद्ग्रहण

स्थानीय क्षेत्र अधिनियम 2001 में वस्तुओं के प्रवेश पर आंध्र प्रदेश कर को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ए. पी. उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा 29.03.2017 पर दिनांकित 29.03.2017 आदेश द्वारा दरकिनारा कर दिया गया था, जो उस संशोधन के बहुत बाद है जो 16.09.2016 पर प्रभावी हुआ था। इस बीच, स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर आंध्र प्रदेश कर अधिनियम, 2001, जिसे असंवैधानिक घोषित किया गया था, को भी तेलंगाना राज्य द्वारा जी. 0 द्वारा अपनाया गया था। एम No.45 दिनांकित 01.06.2016।

47. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया था और इस तरह कानून की पुस्तक से मिटा दिया गया था, ऐसे कानून को 'लागू कानून' के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि संशोधन के तहत विचार किया गया है। तदनुसार, जहां 2001 का स्थानीय क्षेत्र

अधिनियम में वस्तुओं के प्रवेश पर आंध्र प्रदेश कर संशोधन के प्रारंभ से ठीक पहले की तारीख को लागू नहीं था, वहां ऐसा विधान किसी भी मामले में संशोधन के तहत विचार किए गए तरीके से लागू नहीं रह सकता है।

48. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तेलंगाना राज्य द्वारा स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2001 में वस्तुओं के प्रवेश पर आंध्र प्रदेश कर को अपनाना भी उतना ही असंवैधानिक था जितना कि स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2001 में वस्तुओं के प्रवेश पर आंध्र प्रदेश कर को पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तदनुसार, एक मृत कानून होने के कारण, इसे तेलंगाना राज्य द्वारा 01.06.2016 पर अपनाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा, इस अदालत का बाद का निर्णय जिसने माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया, जीवन की सांस नहीं ले सकता है और गोद लेने को मान्य नहीं कर सकता है क्योंकि यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि वैधता

विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए जाने के समय किसी कानून का परीक्षण किया जाना है। एक अधिग्रहण के बाद की शक्ति अधिनियमित होने पर एक कानून को अमान्य प्रमाणित नहीं कर सकती है।

27 2007 एससीसी ऑनलाइन एपी 1158:(2008) 13 वीएसटी 15

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

49. स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2001 में वस्तुओं के प्रवेश पर तेलंगाना कर की धारा 6 में मूल्यांकन, विवरणी आदि के संबंध में तेलंगाना वैट अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं। तदनुसार, वर्तमान 'निगमन द्वारा विधान' का मामला है। इस आधार पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तेलंगाना वैट अधिनियम में संशोधन का स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2001 में वस्तुओं के प्रवेश पर तेलंगाना कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस तरह 4 से 6 साल की सीमा अवधि में विस्तार प्रवेश कर के संबंध में किए गए मूल्यांकन पर लागू नहीं होगा। यह मध्य राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत पर आधारित है।

प्रदेश बनाम एम. वी. नरसिम्हन (इसके बाद, "एम. वी. नरसिम्हन") 28

कि जहां बाद के अधिनियम में पिछले अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया गया है, तो उधार लिए गए प्रावधान बाद के अधिनियम का एक अभिन्न और स्वतंत्र हिस्सा बन जाते हैं और पिछले अधिनियम में किसी भी निरसन या संशोधन द्वारा पूरी तरह से अप्रभावित होते हैं। इस सिद्धांत का अपवाद है:

(i) जहां बाद का अधिनियम और पिछला अधिनियम एक दूसरे के पूरक हैं;

((ख) जहां दोनों अधिनियम समान हैं;

((ग) जहां पिछले अधिनियम में संशोधन यदि बाद के अधिनियम में भी शामिल नहीं किया गया है, तो बाद के अधिनियम को पूरी तरह से अव्यवहारिक और अप्रभावी बना देगा;

((iv) जहां पिछले अधिनियम का संशोधन, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से, उक्त प्रावधानों को बाद के अधिनियम पर लागू होता है।

50. वर्तमान मामले में, चूंकि एम. वी. नरसिम्हन (उपरोक्त) में इस अदालत द्वारा निर्धारित अपवादों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए तेलंगाना वैट अधिनियम में संशोधन स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2001 में वस्तुओं के प्रवेश पर तेलंगाना कर पर लागू नहीं होगा और इस तरह पूरी मांग किसी भी मामले में सीमा द्वारा वर्जित है।

51. धारा 19 के पीछे का इरादा पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करों को शामिल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना और राज्यों के लिए एस. जी. एस. टी. लागू करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संशोधन या निरसन करना था। यह राज्यों को अपने कानूनों में स्वतंत्र रूप से संशोधन करने की अनुमति देने के लिए नहीं था जब तक कि जी. एस. टी. कानून लागू नहीं हो जाते। पोस्ट 16.09.2016

28 (1976) 1 एससीआर 6 173

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 174

राज्यों को 101 वें सी. ए. ए. द्वारा संशोधित संविधान की प्रविष्टि 54 सूची II में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं पर स्वतंत्र रूप से कानून बनाने की कोई क्षमता नहीं थी। धारा 19 का उद्देश्य केवल राज्यों को 101 वें सी. ए. ए. द्वारा संशोधित संविधान के अनुपालन में अपने कानूनों को लाने की अनुमति देना था। धारा 19

अनुच्छेद 243ZT के साथ समान सामग्री है। विपुलभाई एम. चौधरी बनाम गुजरात मिल्क एम. के. टी. जी. फेडरेशन लिमिटेड 29 (इसके बाद, "विपुलभाई") में, यह देखा गया था,

अनुच्छेद 243 जेड. टी. के संदर्भ में, जिसमें संशोधन अधिनियम से पहले राज्यों में लागू सहकारी समितियों से संबंधित कानूनों को संवैधानिक अवधारणा और सहकारी समितियों की स्थापना के अनुरूप होने की आवश्यकता थी और एक वर्ष की अवधि प्रदान की गई थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "संविधान सक्षम बनाता है

संवैधानिक अधिदेश के अनुरूप अपने कानूनों में मौजूदा प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सक्षम विधायिका या प्राधिकरण।"

52. तेलंगाना संशोधन अधिनियम जिस हद तक 7 वीं अनुसूची की सूची I की पूर्व प्रविष्टि 54 के आधार पर कानून बनाने का प्रयास करता है, वह विधायी क्षमता से वंचित है। धारा 19 "सक्षम विधायिका" द्वारा संशोधन पर विचार करती है। संशोधन के बाद योग्यता का निर्धारण संशोधन के बाद के प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्यों के पास राज्य

अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने या निरस्त करने के लिए केवल एक आकस्मिक शक्ति के रूप में विधायी क्षमता थी ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप लाया जा सके। एक वैध संशोधन का एक उदाहरण तेलंगाना वैट अधिनियम में "वस्तुओं" की अवज्ञा में संशोधन करना होता। हालाँकि तेलंगाना वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 ("टी. जी. एस. टी. अधिनियम") के S.174 (1) (आई) द्वारा 7 वीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए तेलंगाना वैट अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। 101 वें संशोधन की धारा 19 संविधान 122 वें संशोधन विधेयक, 2014 के खंड 20 के समान है। उक्त विधेयक पर राज्यसभा की प्रवर समिति ने अपनी दिनांकित 22.07.2015 रिपोर्ट में विचार किया था।

53. निर्धारित यह भी तर्क देते हैं कि सीमा का विस्तार अवधि को बढ़ाकर राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तर्क मान्य नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। आगे यह तर्क कि आकलन आदि पर सीमा के प्रावधान केवल प्रक्रियात्मक हैं और शुल्क और मूल्यांकन के पहलू पर्याप्त नहीं हैं, भी असमर्थनीय है।

29 2015 (3) एससीआर 997

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

54. यह तर्क दिया गया था कि तेलंगाना अध्यादेश 17.6.2017 से प्रभावी अधिनियम के साथ जारी किया गया था। हालाँकि, तेलंगाना संशोधन अधिनियम की धारा 7 ने स्पष्ट रूप से किसी भी बचत खंड के बिना अध्यादेश को निरस्त कर दिया। इसके अलावा, धारा 1 (2) के तहत तेलंगाना संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी रूप से 17.6.2017 से प्रभावी माना गया था। इस प्रकार, तेलंगाना संशोधन का स्पष्ट रूप से उद्देश्य अध्यादेश को पूरी तरह से समाप्त करना था न कि केवल कानून को जारी रखना। इस प्रकार, इस अधिनियम के लिए सभी प्रस्तुतियाँ कि अध्यादेश जारी करना और इसे एक अधिनियम में शामिल करना एक एकल कानून बनाने की शक्ति का गठन करता है जिसका प्रयोग किसी एजेंट के कार्यों की पुष्टि करने वाले प्रमुख के समान किया जा रहा है, राज्य संशोधन के प्रावधानों द्वारा ही गलत हैं।

55. इस प्रकार, विधायी क्षमता की कमी तत्काल है। वह धारा 19 का विषय नहीं है। इसके बजाय, धारा 19 के तहत जो निलंबन में रखा गया है, वह उन अधिनियमों पर ऐसी अक्षमता का प्रभाव है जो संशोधन से पहले ही पारित किए जा चुके थे, यानी लागू अधिनियम। धारा 19 अनुच्छेद 243 जेड. एफ. के समान है और इसे बोंडू रामास्वामी बनाम बेंगलोर के अनुसार उपरोक्त व्याख्या दी जानी चाहिए।

विकास प्राधिकरण 30 (इसके बाद, "बोंडू रामास्वामी")

धारा 1 (2) में "लागू होगा" शब्दों का कोई अर्थ नहीं होगा यदि धारा 19 की व्याख्या इस अर्थ में की जाती है कि संशोधन के संचालन पर ही एक वर्ष की अवधि के लिए रोक लगाई जानी है।

56. वकील ने कहा कि एक संक्रमणकालीन प्रावधान का उपयोग तिरछे उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी कानून में 'संशोधन' करने की शक्ति का दायरा विधायी क्षमता के दायरे के साथ समाप्त हो जाता है और इस तरह के संशोधन की तारीख को ऐसी क्षमता से आगे नहीं बढ़ सकता है। 16.09.2016 से प्रभावी होने के साथ, और इसलिए, 17.06.2017 के अनुसार, राज्य विधानमंडल की अनुच्छेद 246 (3) के संबंध में कानून बनाने की क्षमता मौजूद नहीं थी, जिसे बिना संशोधन वाली प्रविष्टि 54 के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए धारा 9 में 'संशोधन' शब्द को 17.06.2017 पर राज्य विधानमंडल की क्षमता से अधिक व्यापक नहीं माना जा सकता है। इसके बजाय, 'संशोधन' शब्द केवल प्रविष्टि 54 की नई रूपरेखाओं के संबंध में कानून बनाने की शक्ति तक सीमित है। 'टिल' शब्द इंगित करता है कि एक असंगत कानून का जीवनकाल धारा 19 द्वारा तुरंत तय किया जाता है। एक असंगत कानून तब तक लागू रहता है जब तक कि:

30 (2010) 6 एससीआर 29 175

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 176

ए। राज्य विधानमंडल असंगत कानून में संशोधन करता है ताकि इसे 101 वें संशोधन द्वारा संशोधित संविधान के अनुरूप लाया जा सके।

बी। राज्य विधानमंडल असंगत कानून को निरस्त करता है या

ग. अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है अर्थात् 15.09.2017।

57. 'संशोधन' शब्द का उपयोग करने का उद्देश्य राज्य विधानमंडल को 101 वें संविधान संशोधन के अनुरूप मौजूदा कानूनों को लाने की अनुमति देना है ताकि वे काम करना जारी रख सकें। यदि विधानसभाएँ इस तरह का मार्ग चुनती हैं, तो संशोधन पर अधिनियम के असंगत प्रावधान अस्तित्व में नहीं रहते हैं। धारा 19 की भाषा में-जब तक इसमें संशोधन नहीं किया गया। इसलिए, राज्य विधानमंडल के पास नए और सीमित प्रविष्टि 54 में शामिल वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं के संबंध में कोई विधायी क्षमता नहीं थी, या तो अध्यादेश की तारीख को, यानी 17.06.2017, या संशोधन अधिनियम की तारीख को, यानी 02.12.2017।

58. तेलंगाना वैट अधिनियम 2005 को टी. जी. एस. टी. अधिनियम 2017 की धारा 174 (1) (i) द्वारा सूची II की प्रविष्टि 54 में शामिल वस्तुओं के संबंध को छोड़कर प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था। धारा 174 (1) 101 वें संशोधन की स्पष्ट स्वीकृति और स्वीकृति के रूप में कार्य करती है। इसलिए, सभी वस्तुओं पर लागू 02.12.2017 का TVAT संशोधन इस तरह के निरसन के बाद नहीं किया जा सकता है।

59. अनुच्छेद 246 ए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा एक साथ शुल्क लगाने के सिद्धांत का प्रतीक है और सहमति के सिद्धांत से अलग है। अनुच्छेद 246 ए विधान की शक्ति और विषय

वस्तु दोनों का निर्माण करता है। यह इसे 246 (2) के तहत कानून की समवर्ती शक्ति से अलग बनाता है, जिसके लिए किसी को सूची III, अनुसूची VI की यात्रा करने की आवश्यकता होती है और उन विषयों की जांच करने की आवश्यकता होती है जिनके संबंध में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जब एक सिद्धांत के रूप में सहमति पहले से ही इस तरह से मौजूद है, तो संविधान के एक ही अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 246 ए में शक्ति और विषय वस्तु दोनों को रखने के संसद के निर्णय से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग संसद और राज्य द्वारा एक साथ किया जाना है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है जैसा कि वे अनुच्छेद 246 (3) के प्रावधानों के तहत करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

60. इसलिए, राज्य विधानमंडल वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में अपनी कर लगाने की शक्तियों का प्रयोग या तो अनुच्छेद 246 ए के तहत कर सकता है, जिसका प्रयोग संसद के साथ किया जाना है, या अनुच्छेद 246 (3) आर/डब्ल्यू के तहत संशोधित प्रविष्टि 54 केवल उसमें उल्लिखित छह मदों के संबंध में कर सकता है।

61. महाराष्ट्र के कर निर्धारकों की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने अपने मौजूदा बिक्री कर कानूनों, इस मामले में, महाराष्ट्र वैट अधिनियम, 2002 के संबंध में कानून बनाने की राज्य की शक्ति को बनाए रखने के लिए गलती से आगे बढ़ा। उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि अनुच्छेद 246-ए का पहले के बिक्री कर कानूनों से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह विशेष रूप से जी. एस. टी. से संबंधित है, जिसे संविधान के तहत विशेष रूप से "वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति" पर कर के रूप में परिभाषित किया गया था। पीठ और पदार्थ परीक्षण को लागू करते हुए, अनुच्छेद 246-ए में निर्दिष्ट "वस्तु और सेवा कर" वाक्यांश पूरी तरह से अलग है और राज्य विधानमंडल द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाए गए पहले के कर से अलग है।

62. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जीएसटी "आपूर्ति" पर एक कर है। 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले मौजूद कर योग्य घटनाओं के विपरीत, आपूर्ति नई कर योग्य घटना है। केवल यह तथ्य कि "आपूर्ति" शब्द को जी. एस. टी. अधिनियमों के तहत जी. एस. टी. के उद्ग्रहण और मूल्यांकन के उद्देश्य से निर्माण, सेवा और बिक्री को शामिल करने के लिए अवहेलना की गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को भी व्यापक रूप से जी. एस. टी. अधिनियमों के उद्देश्यों की अवहेलना पर निर्भर किया जाना चाहिए, न कि भारत के संविधान पर।

63. इसके अलावा, उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 367 सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधान को शामिल करता है और उन्हें संविधान पर लागू करता है। यह इस संदर्भ में है कि सामान्य खंड अधिनियम के प्रभाव की दो स्तरों पर जांच की जानी चाहिए। एक 101 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2016 के संदर्भ में और दूसरा एम. वी. ए. टी.

अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में। 101 वें संवैधानिक संशोधन के संबंध में, पुराने अनुच्छेद 246 के तहत शक्ति को सूची-II की प्रविष्टि-54 में कानून के पहलुओं को सुधारने के साथ-साथ संक्षिप्त कर दिया गया है, जिसे उसमें संदर्भित किया गया है। इस मामले में, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के प्रावधानों को लागू करके भी, वर्तमान में प्रविष्टि-54 द्वारा कवर किए गए 6 के अलावा शेष वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने की किसी भी शक्ति का कोई सवाल ही नहीं है, जो संशोधन के बाद भी बनी रहती है।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 178

177

64. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. ए. ए. की धारा 19 राज्य विधानसभाओं/संसद को संशोधन अधिनियम को लागू करने के समय लागू कानूनों में कोई भी और हर संशोधन करने के लिए असंबद्ध या व्यापक शक्तियां प्रदान नहीं करती है। धारा 19 में निर्दिष्ट शक्ति राज्य विधानमंडल को एक सीमित अवधि के लिए ऐसी संशोधन करने के लिए दी गई एक सीमित शक्ति है जो विसंगतियों को दूर करने, यदि कोई हो, और मौजूदा कानूनों को जी. एस. टी. विधानों के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल महाराष्ट्र में अपने मौजूदा कानूनों को जी. एस. टी. प्रावधानों के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियमित संरेखण अधिनियम को लागू करने की शक्ति को धारा 19 के अंतराल के रूप में सहेजा जाएगा। नतीजतन, महाराष्ट्र राज्य के पास विवादित संशोधन करने की शक्ति नहीं थी, जो किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र अधिनियम के तहत एक नियमित संशोधन के रूप में अधिनियमित किए गए थे।

65. गुजरात बैंच की अपीलों में पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि गुजरात मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे इसके बाद "गुजरात वैट अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) में विवादित धारा 84 ए को गुजरात मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा राजपत्रित किया गया था, लेकिन "आईडी1" से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, जिसमें यह अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान किया गया है कि यदि "कुछ अन्य कार्यवाही" में किसी विशेष मुद्दे के लिए एक निचले मंच ने एक निर्णय दिया है जो राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है और इस तरह के निर्णय के खिलाफ अपील उच्च मंच के समक्ष लंबित है, तो संशोधन के लिए सीमा की अवधि की गणना करते समय इस तरह के मुकदमे में खर्च की गई अवधि को बाहर रखा जाएगा। पूर्वव्यापी प्रभाव वाला ऐसा प्रावधान देकर राज्य विधानमंडल ने इस प्रकार उन आकलनों को फिर से खोलने में सक्षम बनाने की कोशिश की जो इस तरह के संशोधन को लागू करने से पहले ही वास्तविकता प्राप्त कर चुके थे।

66. गुजरात वैट अधिनियम की विवादित धारा 84 ए को बचाने के लिए धारा 19 को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि सी. ए. ए. की धारा 19 का 1 वर्ष के लिए या कार्यान्वयन की तारीख या जी. एस. टी. व्यवस्था यानी 1.7.2017 जो भी पहले हो, तक सीमित शेल्फ जीवन था और गुजरात अधिनियम की विवादित धारा 84 ए को 06.04.2018 पर अधिनियमित किया गया था, यानी धारा 19 की समाप्ति के बहुत बाद। 67. यह तर्क दिया गया कि किसी भी मामले में गुजरात वैट अधिनियम की धारा 84 ए स्पष्ट रूप से मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी)

का उल्लंघन करती है। जब किसी विशेष वर्ष के लिए मूल्यांकन वास्तविकता प्राप्त करता है तो यह विक्रेता के पक्ष में एक निहित अधिकार पैदा करता है। व्यापारी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपने एफ़ एयर की व्यवस्था करता है कि उसकी देनदारी उस अवधि के लिए स्पष्ट हो गई है जब

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

आकलन ने वास्तविकता प्राप्त कर ली है। बिना किसी समय सीमा के ऐसी स्थिति में परिवर्तन केवल इस आधार पर किया जाता है कि किसी अन्य मामले में न्यायालय द्वारा राजस्व के पक्ष में निर्णय दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध है। इसके अलावा, विवादित प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2006 पेश किया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध होने के रूप में खारिज कर दिया है।

68. यह तर्क दिया जाता है कि यदि अन्य विक्रेताओं के मामले में निर्णयों के आधार पर किसी भी मामले में मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन/संशोधन के लिए राजस्व के लिए एक असीमित समय अवधि उपलब्ध है, तो अकल्पनीय अराजकता पैदा होगी और इसलिए इसे स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है। मफतलाल इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की माननीय 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से प्रत्यर्थी को चारों ओर से समर्थन प्राप्त है। उस मामले में, इस न्यायालय को वर्तमान मामले के विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ा था, जितना कि निर्धारिती अन्य निर्धारिती के मामले में दिए गए निर्णयों के आधार पर कई वर्षों के बाद धनवापसी का दावा करते थे। इस अदालत ने कहा कि अन्य मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर सीमा की निर्धारित अवधि से अधिक धनवापसी के दावों की अनुमति देने से कानून के कई अच्छी तरह से स्वीकृत सिद्धांतों के लिए हिंसा होगी। यह आगे देखा गया कि सार्वजनिक नीति पर आधारित कानून के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक, किसी भी कार्यवाही की वास्तविकता से जुड़ी पवित्रता है, चाहे वह मुकदमा हो या कोई अन्य कार्यवाही।” बाद के निर्णयों के आधार पर कई वर्षों के बाद धनवापसी का दावा करने की प्रथा की वैधता की निंदा करते हुए यह देखा गया कि अदालत का कोई आदेश या डिक्री केवल इसलिए निष्क्रिय या अप्रवर्तनीय नहीं हो जाती है क्योंकि बाद के समय में, कानून के बारे में एक अलग दृष्टिकोण लिया जाता है और यदि यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है। यह अकल्पनीय अराजकता की ओर ले जाएगा।

69. गुजरात वैट अधिनियम की धारा 64 डीलर को संबंधित लेखा वर्ष के अंत से केवल 6 साल की अवधि के लिए खातों की पुस्तकों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके लिए परंतुक में लेखा पुस्तकों के और अधिक संरक्षण की आवश्यकता केवल उस हद तक है जब तक कोई मामला अपील या संशोधन में लंबित है। हालांकि, विवादित प्रावधान डीलर को एक अनिश्चित अवधि के लिए मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन/संशोधन के लिए उजागर करता है जो अत्यधिक और असमान है। वास्तव में, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.4.2006 प्रावधान का पूर्वव्यापी संचालन उन वर्षों के आकलन को फिर से खोलने की अनुमति देता है जिनके संबंध में एक व्यापारी को लेखा पुस्तकों को संरक्षित करने की

आवश्यकता नहीं थी और इसलिए पूर्वव्यापी संचालन सभी अधिक कठिन और स्पष्ट रूप से मनमाना है।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 180

179

V. विश्लेषण और तर्क

70. तेलंगाना बैच के मामलों में तथ्य यह है कि राज्य वैट अधिनियम में संशोधन को दो प्रावधानों तक सीमित कर दिया गया था जो धारा 21 और 32 हैं। उनका प्रभावी अधिनियम पुनर्मूल्यांकन की सूचना जारी करने और मामलों को फिर से खोलने के साथ-साथ लंबित संशोधनों और कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए सीमा की अवधि को बढ़ाने या बढ़ाने के लिए था। मौजूदा कानून में ये चार साल की समय सीमा के अधीन थे। संशोधन के आधार पर, इन्हें दो साल (यानी छह साल) की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। यह तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय बन गया जिसकी परिणति विवादित फैसले में हुई।

71. जहाँ तक गुजरात के मामलों का संबंध है, तथ्य यह है कि गुजरात वैट अधिनियम 01.07.2017 पर लागू हुआ था। उस तारीख के बाद, गुजरात विधानमंडल ने राज्य वैट अधिनियम को निरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने मौजूदा वैट अधिनियम की व्याख्या के आधार पर एक मूल्यांकन को बहुत पहले ही रद्द कर दिया था। गुजरात विधानमंडल ने एक नया प्रावधान, धारा 84 ए पेश करके वैट अधिनियम (इसके निरसन के बाद) में संशोधन किया, जिसे पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। इस संशोधन का प्रभाव अपीलीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी अपील या संशोधन के लंबित रहने के दौरान खर्च की गई अवधि को हटाने के लिए था, संशोधन या फिर से खोलने के उद्देश्य से, जिसे राजस्व के हित में फिर से खोलना आवश्यक था। ये उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न आधारों पर चुनौती का विषय बन गए। उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत और तर्कपूर्ण निर्णय द्वारा संशोधन को इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया कि विधायिका में 101 वें संशोधन की धारा 19 को ध्यान में रखते हुए प्रावधान को लागू करने की क्षमता का अभाव है और इसके अलावा संशोधित प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना था।

महाराष्ट्र बैच के मामलों में, कार्यवाही का विषय एम. वी. ए. टी. था और इसमें संशोधन किए गए थे। माल की बिक्री और खरीद में कर संग्रह के संबंध में कानूनों को समेकित करने के लिए एम. वी. ए. टी. 01.03.2005 पर लागू हुआ। 101 एस. टी. सी. ए. ए. आई. डी. 1 में प्रभावी हुआ और सी. ए. ए. द्वारा सूची 2 की प्रविष्टि 54 के तहत वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर लगाने की राज्य सरकार की शक्ति को केवल उसमें उल्लिखित 6 वस्तुओं के संबंध में प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने एम. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 26 में संशोधन किया और धारा 6 ए, 6 बी और 6 सी को जोड़ा जिसमें निर्धारिती को विवादित कर राशि का 10 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें विफल रहने पर संबंधित निर्धारिती की अपील खारिज कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने किए गए संशोधन को बरकरार रखा

एम. वी. ए. टी. अधिनियम में अपील दायर करने से पहले निर्धारिती को विवादित राशि का 10 प्रतिशत जमा करने की आवश्यकता होती है।

A. धारा 19 की व्याख्या

72. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम की धारा 19 की भाषा अन्य प्रावधानों के विपरीत संविधान के मुख्य भाग से खुद को नहीं जोड़ती है। आगे तर्क यह था कि संशोधन करने की शक्ति को संदर्भ में देखा जाना चाहिए। संशोधन के अन्य प्रावधानों ने संविधान के नए प्रावधानों को शामिल किया। उन्होंने कराधान की प्रविष्टियों को भी काफी हद तक बदल दिया, विशेष रूप से राज्य सूची की प्रविष्टि 54 को मान्यता से परे कर दिया, जिससे राज्यों को अधिकांश वस्तुओं पर वैट लगाने की शक्ति से वंचित कर दिया गया। वे प्रावधान संशोधन यानी 16.09.2016 को लागू करने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए धारा 19 की प्रासंगिक व्याख्या का अर्थ यह होगा कि इसने मौजूदा कानूनों के संचालन को तब तक संरक्षित रखा जब तक कि उन्हें निरस्त नहीं कर दिया गया या ऐसे कानूनों को संशोधन के अन्य प्रावधानों के अनुरूप नहीं लाया गया जो संविधान का हिस्सा बन गए। इस संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 19 को संविधान का एक हिस्सा नहीं माना जा सकता है, बल्कि केवल सीमित संचालन के साथ एक आकस्मिक प्रावधान के रूप में माना जा सकता है।

73. धारा 19 तीन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। पहला, राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के संबंध में मौजूदा स्थिति को संशोधन शुरू होने की तारीख से एक साल की अवधि के लिए या एक नया कानून लागू होने तक, जो भी पहले हो, बनाए रखना है। दूसरा सक्षम विधानमंडलों यानी राज्य विधानमंडलों और संसद को उन मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिए अधिकृत करना है जो राज्यों और देश के अन्य हिस्सों (जाहिर तौर पर केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों) में लागू थे। तीसरा ऐसे कानूनों को निरस्त करना था। अब, इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि धारा 19 संक्रमणकालीन थी। इसकी अनुपस्थिति में, कई सैकड़ों राज्य अधिनियम और केंद्रीय कानून जो लागू थे, खतरे में पड़ जाते। धारा 19 के अलावा कोई बचत प्रावधान नहीं है जो संशोधन का हिस्सा है। यह संदिग्ध है कि क्या सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 अपने बल पर लागू होती। नतीजतन, संसद ने एक घटक क्षमता में कार्य करते हुए संविधान के मूल भागों में संशोधन किया, और साथ ही साथ धारा 19 के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान के संशोधित भागों के अनुसार कानूनी व्यवस्था में बदलाव होने तक मौजूदा कानूनों का सीमित संचालन जारी रहे। यह ध्यान में रखते हुए कि संशोधन ने राज्यों और यहां तक कि संसद को पहले से मौजूद 181 के संबंध में विधायी अधिकार से वंचित कर दिया।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 182

(अर्थात् पूर्व-संशोधन) शक्तियाँ और कराधान के अन्य पहलू, इस तरह के संक्रमणकालीन प्रावधान का अभाव विनाशकारी हो सकता है। यह इस संदर्भ में था कि धारा 19 ने यह भी स्पष्ट किया कि न केवल कानूनों को जारी रखा जाना था, बल्कि यह भी कि राज्य और संसद उन्हें संशोधित या निरस्त कर सकते थे।⁷⁴ याचिकाकर्ताओं ने बोंडू रामास्वामी (ऊपर) और विपुलभाई (ऊपर) में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया है। वर्तमान मामले में, इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि धारा 19 भी उन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है अर्थात् विभिन्न कानूनों और देश के अन्य हिस्सों में प्रचलित मौजूदा वित्तीय और कराधान कानूनों का संरक्षण एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए या जब तक कि उन्हें संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा बताया गया अंतर यह है कि संक्रमणकालीन प्रावधान जो उन मामलों में शामिल थे, वे संविधान का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वे संशोधन के लंबे समय बाद भी जारी रहे और अभी भी लागू हैं। जबकि वर्तमान मामले में, धारा 19 का जीवन सीमित है और यह कभी भी संविधान का हिस्सा नहीं बनेगी।

75. सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा है? यह निर्विवाद है कि संशोधन को उस अनुसार अधिनियमित किया गया था जिसे अब घटक शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अनुच्छेद 368 से प्राप्त है। 1971 के संवैधानिक 25 वें संशोधन अधिनियम के बाद अनुच्छेद 368 के वर्तमान ढांचे में बदलाव आया। उस संशोधन से पहले, प्रावधान का शीर्षक "प्रक्रिया" था।

संविधान के संशोधन के लिए "। संशोधन के आधार पर, अनुच्छेद 368 को "संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और

इसके लिए प्रक्रिया "। अनुच्छेद 368 (2) संशोधन की शुरुआत करने के तरीके को रेखांकित करता है यानी एक विधेयक के माध्यम से और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत के रूप में उसकी प्रक्रिया को रेखांकित करता है। विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। मंत्रिमंडल की सिफारिशों के मामले के विपरीत, या जब कोई अन्य विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है, लेकिन वह संशोधन पर "सहमति" देगा। अनुच्छेद 368 के परंतुक के लिए आवश्यक है कि जहां भी संविधान के गणना किए गए प्रावधानों या भागों को संशोधित करने की मांग की जाती है, इसके अलावा संशोधनों की एक श्रेणी है जिसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उनके राज्य विधानसभाओं के प्रस्तावों द्वारा अनुसमर्थित किया जाना है।

76. उस अच्छी तरह से प्रलेखित मार्ग का वर्णन करना अनावश्यक है जिसके कारण अनुच्छेद 368 में संशोधन हुआ और बाद में किए गए संशोधनों या उनके भाग्य में क्या हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

से मुलाकात की। जिस बात को रेखांकित करने की आवश्यकता है वह यह है कि सामान्य विधान के विपरीत, जो संसद या किसी अन्य विधायी निकाय की शक्ति से जुड़ा हुआ है, संशोधन शक्ति अलग है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक घटक है।

शक्ति। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 31 मामले में, सबसे बड़ी पीठ

गठित, इस न्यायालय ने कभी भी (13 न्यायाधीशों) यह घोषणा की कि अनुच्छेद 368 के तहत शक्ति हालांकि घटक है और हालांकि असीम प्रतीत होती है और स्पष्ट रूप से संकुचित नहीं होती है, फिर भी निहित रूप से "आवश्यक विशेषताओं" या "बुनियादी संरचना" सिद्धांत द्वारा सीमित है।

77. संसद के अधिनियम जैसे एक साधारण कानून, एक विधायी अभ्यास का एक उत्पाद है। उस शक्ति का स्रोत संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधानों में या किसी न किसी सूची में सूचीबद्ध विधानों के माध्यम से पाया जाता है। दूसरी ओर संवैधानिक कानून यह है कि यह संविधान से उत्पन्न होता है और राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करता है, उनकी शक्तियों की अवहेलना करता है और मौलिक अधिकारों और अन्य सीमाओं के माध्यम से कार्यपालिका और विधायी शाखाओं के कामकाज पर सीमाएं लगाता है। विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक ही निकाय, विधायी निकाय द्वारा एक साधारण कानून बनाया या बदला जा सकता है। चूंकि संवैधानिक संशोधन देश के मौलिक कानून से संबंधित हैं जो अन्य कानूनों के लिए अधिकार का स्रोत है, इसलिए इसे विशेष प्रक्रिया को पूरा करने के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। 78. घटक शक्ति और विधायी शक्ति के बीच के अंतर पर स्वर्गीय एच. एम. सीरवर्ड ने संवैधानिक कानून में टिप्पणी की थी।

भारत का 32: "घटक शक्ति इसलिए विधायी शक्ति से अलग एक न्यायिक इकाई या श्रेणी। भारत के मामले में संविधान में संशोधन के तीन अलग-अलग तरीके हैं—पहला सबसे आसान या सबसे सरल है जहां राज्यों के पुनर्गठन या राज्यों के नामों को बदलने की मांग की जाती है, उस स्थिति में एक संसदीय अधिनियम पर्याप्त होगा। अन्य मामलों में, संविधान में संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिसमें सदस्य बैठते हैं और मतदान करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी जाती है। विशेष श्रेणी में अनुच्छेद 368 का प्रावधान है, जिसमें न केवल विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया जाना है, बल्कि इसमें अतिरिक्त संशोधन की आवश्यकता भी है।

31 1973 पूरक 1 एससीआर 1

32 4 संस्करण खंड 3 पृष्ठ 3119 183

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 184 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

प्रस्तावों द्वारा राज्य विधानमंडल के आधे हिस्से के अनुसमर्थन और परंतुक को सुरक्षित करना। इस प्रकार अनुच्छेद 368 के संशोधन और संरचना की प्रकृति स्पष्ट रूप से इस बात को सामने

लाती है कि यह दोनों शक्तियों को समाहित करती है और इसमें संशोधन की प्रक्रिया भी शामिल है।”

79. इस अदालत ने अपने फैसले में बताया था कि ए. के. रॉय (उपरोक्त) ने इस मुद्दे के कुछ पहलुओं पर विचार किया था। वहाँ की चुनौती अनिवार्य रूप से तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लिए थी। चुनौती का एक आधार यह है कि इसने अनुच्छेद 22 का उल्लंघन किया है। चूंकि अनुच्छेद 22 को संविधान के 44 वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था और उन संशोधनों के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था, इसलिए उस संविधान संशोधन की धारा 1 (2) को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि संसद को अनुच्छेद 245 द्वारा कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की गई है, वह कानून के उस दायरे के भीतर पूर्ण है जिस पर वह शक्ति काम कर सकती है। वह शक्ति, अनुच्छेद 245 की शर्तों के अनुसार, केवल संविधान के प्रावधानों के अधीन है। घटक शक्ति, उपरोक्त सीमा के अधीन, विधायी शक्ति से कम पूर्ण नहीं हो सकती है, विशेष रूप से जब संविधान में संशोधन करने की शक्ति और कानून बनाने की शक्ति राज्य के एक ही अंग, अर्थात् संसद को प्रदान की जाती है। संसद को अनुच्छेद 365 के तहत अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते समय अनुच्छेद 368 के तहत अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते समय एक अलग प्रक्रिया का पालन करना पड़ सकता है। लेकिन दो अलग-अलग प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करते समय अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करने का दायित्व शक्ति की चौड़ाई में कोई अंतर नहीं ला सकता है। किसी भी स्थिति में, यह पूर्ण है, एक मामले में संविधान की मूल संरचना की बाधाओं के अधीन और दूसरे में, संविधान के प्रावधानों के अधीन।

यह सच है कि संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा ही किया जाना चाहिए और इसे किसी बाहरी एजेंसी को नहीं सौंपा जा सकता है। यह अनुच्छेद 368 (1) से स्पष्ट है जो संसद की घटक शक्ति के दायरे को तुरंत नकारता है और उस शक्ति को संसद तक सीमित करता है। अधिसूचना जारी करने की शक्ति

संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को लागू करना एक घटक शक्ति नहीं है क्योंकि यह अपने साथ किसी भी तरह से संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं रखता है। इसलिए, संसद को यह अनुमति है कि वह किसी बाहरी एजेंसी को संवैधानिक संशोधन को लागू करने की शक्ति प्रदान करे। तत्काल मामले में, वह शक्ति संसद द्वारा राज्य के एक अन्य अंग, अर्थात् कार्यपालिका को प्रदान की जाती है, जो अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार के पक्ष में सशक्तिकरण के कारण संसद संशोधन को लागू करने की अपनी शक्ति को अपरिहार्य रूप से नहीं खोती है। यदि केंद्र सरकार वह करने में विफल रहती है जो संसद के अनुसार उसे करना चाहिए था, तो संसद के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करते

हुए 44 वें संशोधन अधिनियम की धारा (2) को हटाने और उस अधिनियम या उसके किसी भी प्रावधान को लागू करने का अधिकार होगा।”

80. इस न्यायालय की राय में, केवल इस परिस्थिति से कि धारा 19 को संविधान में नहीं जोड़ा जाता है, कोई अंतर नहीं लाएगा। यदि कोई अनुच्छेद 243 जेड. एफ. को बारीकी से देखता है, जिसकी व्याख्या इस न्यायालय ने बोंडू रामास्वामी (ऊपर) और अनुच्छेद 243 जेड. टी. में की है, जिसकी व्याख्या विपुलभाई (ऊपर) में की गई थी, तो उन प्रावधानों के प्रभाव धारा 19 के समान हैं। हालाँकि वे प्रावधान संविधान का हिस्सा बने रहे, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है और वे केवल ऐतिहासिक थे। इसका कारण यह है कि वे एक सीमित अवधि के लिए सक्रिय थे-जैसे धारा 19। हालाँकि, तथ्य यह है कि उन प्रावधानों के साथ-साथ धारा 19 को घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था। इस न्यायालय की राय में धारा 19 की तुलना केवल एक संसदीय अधिनियम से नहीं की जा सकती है। यह कहने में कोई लाभ नहीं हो सकता कि धारा 19 केवल एक विधायी उपकरण नहीं है। इसे 101 वें संविधान संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में अपनाया गया था। निस्संदेह, इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया था। जो भी कारण संसद को इसे संविधान के निकाय से बाहर रखने के लिए प्रेरित करते थे, तथ्य यह है कि इसे उसी संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में पेश किया गया था जिसने संविधान को पूरी तरह से संशोधित किया था। 81. इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि धारा 19 के अलावा धारा 20 (जो 101 वें संशोधन अधिनियम का भी हिस्सा है) के लिए एक और परंतुक है जो इस प्रकार है:

“20. (1) यदि इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई अड़चन उत्पन्न होती है (जिसमें 185 के संबंध में कोई अड़चन भी शामिल है)

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 186 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

संविधान के प्रावधानों से संक्रमण के लिए जो इस अधिनियम द्वारा संशोधित संविधान के प्रावधानों के लिए राष्ट्रपति की सहमति की तारीख से तुरंत पहले थे), राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकता है, जिसमें इस अधिनियम या कानून द्वारा संशोधित संविधान के किसी भी प्रावधान का कोई अनुकूलन या संशोधन शामिल है, जो राष्ट्रपति को इस बाधा को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश ऐसी सहमति की तारीख से तीन साल की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत किया गया प्रत्येक आदेश, इसे बनाए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।”

82. यह विवाद में नहीं हो सकता है कि धारा 20 दो साल की अवधि के लिए अस्तित्व में थी और राष्ट्रपति को संविधान में संशोधनों को लागू करने के दौरान अनुभव किए गए विभिन्न संप्रदायों को

हटाने के लिए आदेश जारी करने में सक्षम बनाती थी। यदि वास्तव में संशोधनों के उन हिस्सों को घटक शक्ति के प्रयोग में नहीं बल्कि केवल विधायी शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित किया गया था, तो धारा 20 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई शक्ति की कोई वैधता नहीं होगी। 83. संशोधन के प्रावधानों की समग्र व्याख्या पर, यह माना जाता है कि धारा 19 और 20 आनुषंगिक और अस्थायी प्रावधानों का गठन करती हैं, जिनका जीवन सीमित है। वे संविधान का हिस्सा बने या नहीं, यह वास्तव में अकादमिक है। वास्तव में जो मायने रखता है वह उन प्रावधानों का प्रभाव है।

B. क्या संशोधन या निरसन की शक्ति धारा 19 के तहत सीमाओं के अधीन है।

84. इस संदर्भ में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 143 (2) पर राम कृष्ण रामनाथ (उपरोक्त) मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा विचार किया गया था। यह प्रावधान इस प्रकार है:

“143(2) कोई भी कर शुल्क, उपकर या शुल्क जो इस अधिनियम के भाग III के प्रारंभ से तुरंत पहले किसी प्रांतीय सरकार, नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा प्रांत, नगरपालिका, जिले या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए उन्नीस सौ पैंतीस जनवरी को लागू कानून के तहत कानूनी रूप से लगाया जा रहा था, उन करों, शुल्कों के बावजूद,

उपकर या शुल्क संघीय विधायी सूची में उल्लिखित हैं, लगाए जाते रहते हैं और उसी उद्देश्य के लिए तब तक लागू होते रहते हैं जब तक कि संघीय विधानमंडल द्वारा इसके विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता है।”

85. राम कृष्ण रामनाथ (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भारत सरकार अधिनियम की धारा 143 (2) में पाए जाने वाले "अधिरोपित किया जाना जारी रखें" वाक्यांश के उपयोग पर विचार करते हुए, जब तक कि संघीय विधानमंडल द्वारा इसके विपरीत प्रावधान नहीं किए जाते हैं, तब तक यह प्रावधान प्रांत में एक सीमित विधायी शक्ति रखता है जो लेवी को जारी रखने या जारी नहीं रखने की इच्छा को इंगित या व्यक्त करता है, जिसमें कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की शक्ति शामिल होगी। इस तरह की सीमित विधायी शक्ति में कर की दर को कम करना भी शामिल होगा, हालांकि शुल्क को जारी रखा जाएगा। ऐसा कहने के बाद, इस अदालत ने देखा कि इस सीमित विधायी प्राधिकरण का प्रयोग कैसे किया जा सकता है:

“संविधान के प्रावधान का प्रभाव कर लगाने की शक्ति को जारी रखने में सक्षम बनाना होगा, लेकिन इससे इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आता है कि इसके निहितार्थ से प्रावधान केंद्रीय विधानमंडल की निरंतरता को समाप्त करने की प्रबल शक्ति के अधीन लेवी को जारी रखने की इच्छा रखने या न रखने की इच्छा रखने के लिए एक सीमित विधायी शक्ति प्रदान करता है और इस सीमित विधायी शक्ति के अस्तित्व के आधार पर ही 1920 के अधिनियम के तहत कर प्रावधान को निरस्त करने के प्रांतीय विधानमंडल के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कोई प्रांतीय विधानमंडल दर को बहुत अधिक मानते हुए कर को जारी रखना चाहता है और चाहता है कि इसे कम किया जाए और उस उद्देश्य के लिए एक

अधिनियम पारित किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कानून अक्षम है और राज्य सरकार को स्थानीय प्राधिकरण को उसी दर से कर लगाने की अनुमति देनी चाहिए जो 1 अप्रैल, 1937 को प्रचलित थी, यदि राज्य सरकार कर को जारी रखना चाहती है। यदि ऐसा विधान शुल्क की दर में कमी प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किया गया था, तो इसकी विधायी क्षमता स्पष्ट रूप से शब्दों में निहित शक्ति के लिए पता लगाने योग्य होनी चाहिए जो एस में "लगाया जा सकता है"। 143(2) भारत सरकार अधिनियम। यदि हम अब तक सही हैं तो यह होगा कि इस सीमित विधायी शक्ति के प्रयोग में प्रांतीय विधानमंडल को भी कर की निरंतरता के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा, यदि निश्चित रूप से, एस की अन्य शर्तें हैं। 143(2) संतुष्ट हैं, अर्थात्, (1) कि कर वह था जो सरकार के भाग III के प्रारंभ में स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कानूनी रूप से लगाया गया था

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शन [एस. रवींद्र भाट, जे.] 188 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

भारत अधिनियम, (2) कि कर एकत्र करने वाले निकाय की पहचान, वह क्षेत्र जिसके लाभ के लिए कर का उपयोग किया जाना है और जिन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है, वही बना रहेगा और (3) कर की दर में वृद्धि नहीं की गई है और न ही इसकी घटना में किसी भी तरह से बदलाव किया गया है, ताकि यह वही कर बना रहे। यदि जैसा कि हम पहले मान चुके हैं कि कर लगाने के संबंध में कानून बनाने के लिए प्रांत में एक सीमित विधायी शक्ति है ताकि इसे जारी रखा जा सके, तो 1949 के अधिनियम की वैधता जो बिना किसी विराम के कर जारी रखने के विधायी इरादे को प्रकट करती है, प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन द्वारा स्थापित की जा रही कानूनी निरंतरता को बनाए रखना होगा।"

86. यह याद रखना सार्थक होगा कि सिंथेटिक्स और केमिकल्स में

लिमिटेड और ओआरएस. वी.यू. पी. और अन्य का राज्य। 33 इस न्यायालय ने कहा कि: "[.....] कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 246 और संविधान के अन्य अनुच्छेदों द्वारा दी गई है। संविधान की सातवीं अनुसूची की तीन सूचियाँ विधायी प्रमुख या विधायी हैं। ये उस क्षेत्र का सीमांकन करते हैं जिस पर उपयुक्त विधानसभाएँ काम कर सकती हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि तीन सूचियों में प्रविष्टियों की भाषा को व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए, लेकिन अलग-अलग सूचियों में या एक ही सूची में इनमें से कुछ प्रविष्टियाँ ओवरलैप हो सकती हैं और कभी-कभी एक-दूसरे के साथ सीधे टकराव में प्रतीत हो सकती हैं, तब और फिर ही अदालत का कर्तव्य आता है कि वह सच्चे इरादे और उद्देश्य को निर्धारित करे और प्रश्न में विशेष कानून की जांच करे। प्रत्येक सामान्य शब्द को उन सभी सहायक या सहायक मामलों तक विस्तारित किया जाना चाहिए जिन्हें इसमें निष्पक्ष और यथोचित रूप से समझा जा सकता है।....."

87. हाल ही में, एल. आर. वी. के माध्यम से बिमोलांग्शु रॉय (मृत) असम राज्य

& 34 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि:

“23. अनुच्छेद 246 भारत के संविधान के तहत कानून बनाने के अधिकार के स्रोतों में से एक है। यह घोषणा करता है कि संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं को सातवीं अनुसूची में निहित तीन सूचियों में से प्रत्येक में "किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति" है। यह भी स्पष्ट करता है कि संसद की शक्ति

33 1989 पूरक (1) एससीआर 623 34 [2017] 13 एससीआर 301

यह सूची I और सूची II के संबंध में राज्य विधानमंडल के संबंध में अनन्य है। सूची III विभिन्न पहलुओं को इंगित करती है जिन पर संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को अनुच्छेद 254 के अनुशासन के अधीन समवर्ती रूप से कानून बनाने का अधिकार होगा। 24. अनुच्छेद 246 में निहित घोषणा के अलावा, संविधान के कई अन्य अनुच्छेद हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में संसद या राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 3 संसद को एक नया राज्य बनाने या मौजूदा राज्य को समाप्त करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। ऐसी शक्ति विशेष रूप से संसद को प्रदान की जाती है।

25. अनुच्छेद 326 लोक सभा या राज्य की विधान सभा के किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक नागरिक के अधिकार की घोषणा करते हुए, उपयुक्त विधानमंडल को कानून बनाकर अनुच्छेद 326 के तहत निर्दिष्ट किसी भी आधार पर ऐसे किसी भी नागरिक को मतदाता होने के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए अधिकृत करता है। इस तरह का कानून बनाने का अधिकार स्पष्ट रूप से सीधे अनुच्छेद 326 के पाठ से है, लेकिन अनुच्छेद 246 से नहीं। अनुच्छेद 2, 3, 11, 15 (5), 22 (7), 32 (3), 33, 34, 59 (3), 70, 71 (3), 98 (2) भी देखें। ऊपर वर्णित लेख केवल उदाहरणात्मक हैं लेकिन श्रेणी के संपूर्ण नहीं हैं।

26. यह याद रखना चाहिए कि इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि सातवीं अनुसूची की विभिन्न सूचियों में प्रविष्टियां विधायी शक्ति के स्रोत नहीं हैं, बल्कि केवल उन विभिन्न शक्तियों का संकेत हैं जो उपयुक्त विधायिका कानून बनाने के लिए सक्षम है।

27. सातवीं अनुसूची में निहित सूचियों में प्रविष्टि के दायरे की पहचान करने में इस न्यायालय का कार्य आसान नहीं है। प्रविष्टियों के दायरे की जांच करते समय इस न्यायालय को अनिवार्य रूप से विचाराधीन प्रविष्टि के संदर्भ में प्रासंगिक संविधान की योजना को ध्यान में रखना चाहिए।

28. तीन सूचियों की योजना से एक व्यापक पैटर्न की पहचान की जा सकती है, जिनकी मुख्य विशेषताएं हैं (i) संघ को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले कानून के क्षेत्र विशेष रूप से संसद को सौंपे गए हैं, (ii) राज्य विधानसभाओं को अमेरिकी संविधान के विपरीत केवल विशिष्ट विधायी कार्य सौंपे गए हैं, (iii) अवशिष्ट विधायी 189

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 190 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

संसद में शक्ति प्रदान की जाती है; (iv) कर प्रविष्टियाँ सामान्य प्रविष्टियों से अलग हैं 24, और (v) सूची III में कर प्रविष्टि नहीं है,

29. साथ ही, यह भी देखा जा सकता है कि सातवीं अनुसूची में निहित तीन सूचियों की योजना में कोई तार्किक एकरूपता नहीं है।”

88. बोंडू रामास्वामी (ऊपर) में विचाराधीन प्रावधान अनुच्छेद 243 जेडई था। इसे भारत के संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था जो 24.04.1993 और 01.06.1993 पर लागू हुआ था। संशोधनों का उद्देश्य-वास्तव में उनके अधिनियमित प्रावधानों के रूप में-नगर पालिकाओं और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक राजनीतिक सरकार और जमीनी स्तर को मजबूत करना था। अनुच्छेद 243 जेडएफ के शब्द वर्तमान मामले में धारा 19 के समान हैं। इस अदालत ने अनुच्छेद 243ZF के प्रभाव पर चर्चा की और निम्नानुसार कहा:

“40. कोई भी कानून या उसका प्रावधान जो किसी भी संवैधानिक प्रावधान से असंगत है, अदालतों द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। नतीजतन, यदि बी. डी. ए. अधिनियम या बी. डी. ए. अधिनियम का कोई प्रावधान संविधान के भाग IX-A के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत पाया जाता है, तो इसे अदालतों द्वारा संविधान के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दिया जाएगा। नगरपालिकाओं से संबंधित किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के संबंध में, अनुच्छेद 243-जेडएफ ऐसी अयोग्यता को निलंबित कर देता है या अमान्यता को 1-6-1993 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर देता है ताकि सक्षम विधानमंडल नगरपालिकाओं से संबंधित ऐसे कानून में संशोधन या निरसन करके विसंगति को दूर करने में सक्षम हो सके ताकि इसे संविधान के भाग IX-A के प्रावधानों के अनुरूप लाया जा सके।

41. अनुच्छेद 243-जेडएफ एक ऐसा प्रावधान है जो नगरपालिकाओं से संबंधित कानून के किसी भी प्रावधान को जारी रखने में सक्षम बनाता है, भले ही ऐसा प्रावधान एक वर्ष की निर्दिष्ट अवधि के लिए संविधान के भाग IX-A के प्रावधानों के साथ असंगत हो। यह नगरपालिकाओं से संबंधित कानूनों के अलावा किसी अन्य कानून को जारी रखने का लाभ नहीं देता है; यह एक वर्ष के लिए किसी कानून को जारी रखने का भी प्रावधान नहीं करता है, यदि उल्लंघन भाग IX-A के अलावा किसी अन्य संवैधानिक प्रावधान के संबंध में है; और यह किसी कानून के किसी भी प्रावधान को इसके साथ असंगत घोषित नहीं करता है और न ही किसी कानून को अमान्य घोषित करता है। अयोग्यता

न्यायालय द्वारा किसी कानून की घोषणा तब की जाती है जब वह किसी कानून या उसके प्रावधान को किसी संवैधानिक प्रावधान के साथ असंगत मानता है।

42. अनुच्छेद 243-जेडएफ का लाभ केवल "नगर पालिकाओं" से संबंधित कानूनों के संबंध में उपलब्ध है। "नगरपालिका" शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है जिसका अर्थ भाग IX-A के तहत इसे सौंपा गया है। अनुच्छेद 243-पी (ई) इस शब्द को अनुच्छेद 243-क्यू के तहत गठित स्वशासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 243-क्यू विशेष रूप से तीन प्रकार की नगर पालिकाओं को संदर्भित करता है, अर्थात्, एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम। इस प्रकार, न तो कोई शहर सुधार न्यास और न ही कोई विकास प्राधिकरण एक नगरपालिका है, जिसे अनुच्छेद 243-जेडएफ में संदर्भित किया गया है। इस प्रकार बी. डी. ए. अधिनियम या उसके किसी भी प्रावधान की वैधता का परीक्षण करने के लिए अनुच्छेद 243-जेड. एफ. की कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि बी. डी. ए. अधिनियम या उसका कोई प्रावधान भाग IX-ए के प्रावधानों के साथ असंगत पाया जाता है, तो ऐसा असंगत प्रावधान 1-6-1993 से भी अमान्य होगा, और अनुच्छेद 243-जेड. एफ. के तहत अनुमत एक वर्ष की अवधि के लिए निरंतरता का लाभ कानून के ऐसे प्रावधान के लिए उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि बी. डी. ए. अधिनियम नगर पालिकाओं से संबंधित कानून नहीं है।

45. भाग IX-A नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करके और न्यूनतम समान मानदंड निर्धारित करके और चुनावों के नियमित और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करके शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक शासन को मजबूत करने का प्रयास करता है। जब भाग IX-A लागू हुआ, तो नगरपालिकाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों के प्रावधान जो भाग IX-A के प्रावधानों के साथ असंगत या विपरीत थे, लागू होना बंद हो गए होंगे। कुछ समय के लिए निरंतरता प्रदान करने और संबंधित राज्य सरकारों को इस बीच भाग IX-A के प्रावधानों के अनुरूप नगर पालिकाओं से संबंधित संबंधित अधिनियमों को लाने का अवसर प्रदान करने के लिए, अनुच्छेद 243-ZF जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य शहर सुधार न्यासों या विकास प्राधिकरणों से संबंधित किसी भी कानून को अमान्य नहीं करना था, जो लेआउट बनाकर और जनता के सदस्यों को भूखंड/घर/अपार्टमेंट उपलब्ध कराकर शहरों के नियोजित विकास के विशिष्ट और विशेष कार्यों के संदर्भ में काम करते हैं।"

89. संविधान में 97 वें संशोधन का प्रभावी अधिनियम, जो 12.01.2012 पर लागू हुआ, प्रावधानों को लागू करने के लिए था, ताकि 191 को मजबूत किया जा सके।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 192

सहकारी समितियों का लोकतांत्रिक, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सुदृढ़ तरीके से कार्य करना। विभिन्न नए प्रावधानों ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX-B को शामिल किया जिसने सहकारी समितियों से संबंधित राज्य कानूनों के लिए कई शर्तों को निर्दिष्ट किया। अनुच्छेद 243 जेडटी, जो वर्तमान मामले की धारा 19 के समान है, ने संशोधित या निरस्त होने तक या संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति तक सीमित अवधि के लिए मौजूदा कानूनों को लागू रखने की मांग की। इस अदालत ने विपुलभाई (ऊपर) में 243 जेडटी की

व्याख्या पर निर्णय दिया कि सक्षम विधायिका संवैधानिक जनादेश के अनुरूप अपने कानूनों में मौजूदा प्रावधानों में उपयुक्त रूप से संशोधन कर सकती है।

90. एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि धारा 19 को घटक शक्ति के हिस्से के रूप में अधिनियमित किया गया था और बाकी संवैधानिक संशोधन के समान बल है और यह केवल एक संसदीय अधिनियम नहीं है, तो इस अनुक्रम के परिणाम पर विचार करना होगा। पिछले निर्णयों में बोंडू रामास्वामी (ऊपर) और विपुलभाई (ऊपर), इंगित करते हैं कि

जिस प्रकार के संक्रमणकालीन प्रावधानों से वे निपटते थे-जिन्हें संविधान के हिस्से के रूप में अधिनियमित किया गया था-राज्यों की संशोधन करने की शक्ति संबंधित संशोधन द्वारा लागू किए गए संविधान के नए प्रावधानों के साथ मौजूदा कानून की असंगति लाने तक सीमित है। उन मामलों में, अदालत का सामना उस प्रकृति की जटिल स्थिति से नहीं हुआ था जिससे आज किसी को निपटना पड़ता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि 101 वें संशोधन ने अप्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था को विशिष्ट रूप से बदल दिया और एक अर्थ में संवैधानिक समझौते को ही संशोधित किया। कराधान सहित विधायी शक्तियों के वितरण के पारंपरिक वर्णन समाप्त हो गए थे, जो अनुच्छेद 245 और 246 में अपनी उत्पत्ति का पता लगाते थे और साथ ही अनुच्छेद 254 द्वारा अधिनियमित तिरस्कार से निपटने के नियम भी। इसके बजाय, जो लाया गया वह नए जोड़े गए प्रावधान अनुच्छेद 246 ए के माध्यम से दोनों राज्य विधानसभाओं और संघ की सामान्य या समवर्ती शक्ति प्राप्त करने की एक पूरी तरह से नई अवधारणा थी।

91. जैसा कि पहले कहा गया था, परिवर्तन नाटकीय और क्रांतिकारी था और बुद्धिमानी से संवैधानिक संशोधन निकाय जो संसद है और अनुसमर्थन करने वाले राज्यों ने यह सुनिश्चित करना समीचीन महसूस किया कि एक वर्ष की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान या जब तक नई जी. एस. टी. व्यवस्था को एक अधिनियम के माध्यम से लागू नहीं किया जाता है, तब तक राज्यों और संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

समय की मांग के अनुसार परिवर्तन करें। पिछले दो निर्णयों में,

बोंडू रामास्वामी (ऊपर) और विपुलभाई (ऊपर), हालांकि, कोई नहीं था

राज्य की शक्तियों को अस्वीकार करने या संसद और राज्य को नई शक्तियां प्रदान करने का सवाल, बल्कि बोंडू रामास्वामी (ऊपर) में पंचायतों और जिला परिषदों के मामले में नए निकायों के निर्माण और सहकारी समितियों के संबंध में विपुलभाई (ऊपर) में नए मानकों को लागू करने का सवाल। फिर, मौजूदा कानूनी व्यवस्था को सीमित अवधि के लिए संरक्षित किया गया था। फिर भी अदालत ने महसूस किया कि संशोधनों का बचत या संक्रमणकालीन प्रावधानों द्वारा प्रदान की गई अवधि से

आगे जाकर स्थायी प्रभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें अनिवार्य रूप से नई व्यवस्था के साथ असंगत नहीं होने के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता।

92. हालाँकि, वर्तमान मामले में, धारा 19 को एक पूर्ण घटक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो संविधान में अन्य सीमाओं के अधीन है, और यह भी दिया गया है कि संशोधन द्वारा राज्य सूची की प्रविष्टि 54 और केंद्रीय सूची की प्रविष्टि 84 में विधायी प्रविष्टियों को काफी हद तक बदल दिया गया था, इस अदालत को इस वास्तविकता को ध्यान में रखना होगा कि राज्य की शक्तियों या यहां तक कि संसद की शक्ति को सीधे संशोधन से प्राप्त किया जाना था।

93. इस तर्क में योग्यता है कि हालांकि अनुच्छेद 246 ए एक तरह से वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति को समझता है, फिर भी इसका संचालन केवल जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों के माध्यम से ही हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जी. एस. टी. परिषद का गठन 101 वें संशोधन के बाद किया गया था, फिर भी, सिफारिशें करने की प्रक्रिया केवल शुरू ही हुई थी। इसलिए, कानून बनाने की शक्ति केवल अनुच्छेद 246 ए से नहीं ली जा सकती थी। इस न्यायालय की राय में कानून बनाने की शक्ति (जो मौजूदा कानूनों में संशोधन या निरसन करना है), तब किसी अन्य प्रावधान से भी प्राप्त हो सकती है। वर्तमान मामले में, धारा 19 को ही वह स्रोत माना जाता है जो संसद और राज्य विधानमंडलों (अनुच्छेद 246 ए के साथ) को मौजूदा कानूनों में संशोधन करने में सक्षम बनाता है। संघ सूची की प्रविष्टि 97 का सादृश्य आकर्षक होगा। संसद के मामले में, यह कहा जा सकता है कि एक बार सेवा कर से संबंधित कानूनों को लागू करने की शक्ति समाप्त हो जाने के बाद, प्रविष्टि 92 सी भी एक अर्थ में, इसके सार से रहित थी। प्रविष्टि 97 अभी भी तर्क दे सकती है कि यह मौजूदा केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने के लिए शक्ति का एक स्रोत हो सकता है। यह व्याख्या व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि धारा 19 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति सक्षम विधायिका है, न कि संसद; अकेले संसद 193 में अधिनियमित कर सकती है।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 194

संघ सूची की प्रविष्टि 97 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग। हालाँकि, यह निष्कर्ष 16.09.2016 पर संशोधन के लागू होने के अनुरूप नहीं होगा। संशोधन या निरस्त करने की शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र सामंजस्यपूर्ण तरीका धारा 19 और अनुच्छेद 246 ए हो सकता है, जिसे मौजूदा स्थिति को जारी रखने में सक्षम बनाने और केंद्र और राज्यों दोनों को संशोधन या निरसन के माध्यम से मौजूदा कानूनों में आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने दोनों शक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए।

94. इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून बनाने का अधिकार संविधान का है। हमारे संविधान के संदर्भ में, यह अधिकार पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से अनुच्छेद 245 और 246 में स्थित है। अदालतों ने लगातार माना है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूचियां केवल कानून के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करती हैं; उन्हें शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं माना जाता है। प्राधिकरण या शक्ति अनुच्छेद 245 और 246 से उत्पन्न होती है। उन विधायी निकायों के पुनर्गठन, विशेष रूप से पहली सूची की प्रविष्टि 84 और दूसरी सूची की प्रविष्टि 54 और दोनों विधायी संस्थाओं यानी संसद और राज्य विधानमंडलों पर बड़ी शक्तियों के अनुरूप होने का अर्थ था कि दोनों प्राधिकरण अनुच्छेद 246 ए के

तहत अप्रत्यक्ष कराधान के उद्देश्य से "वस्तुओं और सेवाओं" के विवरण के भीतर समझे जाने वाले सभी विषयों पर कानून बनाते हैं। फिर भी इस प्रावधान के संचालन के लिए जी. एस. टी. परिषद द्वारा सिद्धांतों के निर्माण की आवश्यकता थी जो बाद में हुआ। संवैधानिक संशोधन के लागू होने और एक व्यापक कानून के अधिनियमन के बीच का अंतराल, [जी. एस. टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर] धारा 19 द्वारा प्रदान किया गया। जैसा कि इस निर्णय के पिछले खंड में अभिनिर्धारित किया गया है, धारा 19 को सीमित अवधि के लिए संविधान के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए जो यह संचालित थी और प्रभावी थी।

95. ऐसा होने पर अनुक्रम यह होना चाहिए कि कानून बनाने का अधिकार धारा 19 के माध्यम से व्यक्त किया जाए, जिसे अनुच्छेद 246 ए के साथ पढ़ा जाए। दूसरे शब्दों में, जी. एस. टी. परिषद द्वारा तैयार किए गए सिद्धांतों के अभाव में, धारा 19 और अनुच्छेद 246 ए द्वारा कानून में संशोधन या निरस्त करने के लिए अधिकार, जैसा कि मूल रूप से समझा जाता था, संविधान से मिटा दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप एक उलझन पैदा हुई होगी। इसलिए, धारा 19 और अनुच्छेद 246 ए को संसद और दोनों के लिए उपलब्ध कानून के एक क्षेत्र को व्यक्त करने के रूप में समझा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

राज्य विधानमंडल यथास्थिति को आगे बढ़ाने के लिए, मौजूदा कर कानूनों के प्रशासन में अप्रत्याशित या अन्य संभावनाओं को पूरा करते हैं। एक उदाहरण यह हो सकता है कि एक भारी वित्तीय बोझ, यह अभिनिर्धारित करने के परिणामस्वरूप डाला जा रहा है कि मौजूदा लेवी के संग्रह के लिए तंत्र दोषपूर्ण था, उच्च न्यायालय ने एक नियम या वैधानिक प्रावधान को अमान्य कर दिया। उस स्थिति में, यदि यह माना जाता कि राज्य में 01.07.2017 तक की अवधि के दौरान कानून बनाने और एक मान्यकारी अधिनियम के माध्यम से दोषों को ठीक करने की पूरी तरह से क्षमता का अभाव है, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। वाक्यांश "संशोधन" या "निरसन" एक विधायी गतिविधि को दर्शाता है। यह कि एक घटक प्रक्रिया के माध्यम से पेश किए गए प्रावधान में इसका उल्लेख किया गया है, इसका मतलब है कि इसे अर्थ दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी शब्द या प्रावधान को अधिशेष नहीं माना जा सकता है।

96. 'संशोधन' शब्द का अर्थ सर्वविदित है कि यह कुछ सुधारने, कुछ जोड़ने, हटाने, या कुछ प्रतिस्थापित करने या किसी मौजूदा दस्तावेज़, अधिनियम या नियम को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने के विचार को अपने दायरे में लेता है। पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस लॉ लेक्सिकन 35 में यह कहना है:

“संशोधन/निरसन। वास्तव में, संशोधन एक व्यापक अवधि है और इसमें मौजूदा कानून के किसी प्रावधान को निरस्त करना या हटाना शामिल है। यदि किसी मौजूदा कानून का संशोधन छोटा है, तो अधिनियम संशोधन करने का दावा करता है; यदि यह व्यापक है, तो यह एक कानून को

निरस्त करता है और इसे फिर से लागू करता है।निरसन और संशोधन के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है।भागवत राम शर्मा बनाम यूओआई, एआईआर 1988 एससी 740,746.9

संशोधन करें।फ्रांसीसी शब्द से लिया गया एक शब्द जिसका अर्थ है 'बेहतर बनाना'; 'बेहतरी के लिए बदलना'।'

औपचारिक रूप से कुछ जोड़, चूक या प्रतिस्थापन [प्रस्तावना, टी. पी. अधिनियम (1882 का 4)] द्वारा परिवर्तन करना।

संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संविधान में 'संशोधन' करने की शक्ति मौलिक अधिकारों को छीनने की शक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।[शंकरी प्रसाद सिंह बनाम यू. ओ. आई., ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 458] 'संशोधन' शब्द का शब्दकोश अर्थ किसी गलती या सुधार को ठीक करना है; लेकिन शब्दकोश पर अनुच्छेद 368 की निर्भरता के संदर्भ में।

35 पी. रामनाथ अय्यर, एडवांस लॉ लेक्सिकन, खंड I पृष्ठ 271195 पर

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 196

शब्द का अर्थ एकमात्र रूप से अनुचित है, क्योंकि अनुच्छेद 368 जो करने के लिए अधिकृत करता है वह संविधान के प्रावधानों का संशोधन है।एक उचित मामले में एक कानून के संशोधन में कानून के किसी एक या अधिक प्रावधानों को हटाना और उनके नए प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापन शामिल हो सकता है।इसी तरह संविधान के किसी संशोधन में, जो अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त शक्ति का विषय है, प्रावधानों में संशोधन या परिवर्तन या यहां तक कि एक संशोधन भी शामिल हो सकता है जो उक्त प्रावधानों को कुछ मामलों में लागू नहीं करता है।संदर्भ में संशोधन करने की शक्ति एक बहुत व्यापक शक्ति है और इसे शब्द 'संशोधन' के शाब्दिक शब्दकोश अर्थ द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मैड एलजे:क्यू. डी. (1961-1965) खंड II सी 1204-1205:(1965) 1 एससीजे 377: (1965)1 मैड एलजे (एससी) 57:ए. आई. आर 1965 एस. सी. 845

संशोधन; संशोधन; सुधार; सुधार।ये सभी शब्द व्यक्त करते हैं

किसी चीज को अधिक परिपूर्ण स्थिति में लाने का विचार।हम तब सुधार करते हैं जब हम चीजों को किसी मानक या नियम के अनुरूप बनाते हैं; जैसे कि प्रूफ शीट को सही करने के लिए।हम किसी डिफ़ॉल्ट या कानून में संशोधन करने के लिए दोषों या त्रुटियों को दूर करके संशोधन करते हैं।एमेन्ड संशोधन का एक अन्य रूप है और इसे ज्यादातर पुस्तकों के संस्करणों पर लागू किया जाता है।सुधार का अर्थ है एक नए और बेहतर रूप में अपन जीवन में सुधार लाना।सुधार करना सही करना है, जैसे, किसी गलती को सुधारना, दुरुपयोग को सुधारना।

एक उचित मामले में कानून के संशोधन में कानून के किसी एक या अधिक प्रावधानों को हटाना और उनके नए प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापन शामिल हो सकता है। संविधान का एक संशोधन, जो अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त शक्ति का विषय है, में संशोधन या प्रावधानों में परिवर्तन या यहां तक कि एक संशोधन भी शामिल हो सकता है जो उक्त प्रावधानों को कुछ मामलों में लागू नहीं करता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845,854. [भारत का संविधान, अनुच्छेद 368]

कलकत्ता त्रिका किरायेदारी संशोधन अधिनियम की धारा 1 (2) में संशोधित शब्द का प्राकृतिक अर्थ 'जोड़, प्रतिस्थापन और चूक द्वारा परिवर्तित' के रूप में किया जाना चाहिए। देवराज देवी बनाम सत्यदर्शन, ए. आई. आर. 1954 कैल 119।"

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

97. इसलिए, यह माना जाता है कि संशोधन की धारा 19 (अनुच्छेद 246 ए के साथ पढ़ें) के तहत कोई सीमाएं नहीं थीं। यह प्रावधान मौजूदा कानूनों में संशोधन के माध्यम से आवश्यक परिवर्तन करने के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए उपलब्ध संप्रभु विधायी शक्ति की अभिव्यक्ति का गठन करता है। जैसा कि राम कृष्ण रामनाथ (ऊपर) में संक्रमणकालीन शक्ति (उस मामले में, धारा 143 (3)) "इसके द्वारा प्रावधान

निहितार्थ इच्छा करने या न करने के लिए एक सीमित विधायी शक्ति प्रदान करता है

शुल्क की निरंतरता।" यह सीमित विधायी शक्ति राज्यों द्वारा कथित तरीके से संकुचित या सीमित नहीं थी। यह संकेतित समय सीमा (यानी एक वर्ष, या नया जी. एस. टी. कानून लागू होने तक) द्वारा सीमित है। इसलिए, यह संशोधित संविधान के अनुरूप मौजूदा प्रावधानों को लाने के अलावा अन्य प्रावधानों को लागू कर सकता है।

ग. तेलंगाना अधिनियम की वैधता का परीक्षण एक अध्यादेश के रूप में इसके उद्भव के स्पर्श पत्थर से किया गया

98. तेलंगाना ने तर्क दिया था कि हालांकि 1 जुलाई 2017 से प्रभावी होने के साथ, सी. जी. एस. टी. अधिनियम के अधिनियमन के कारण, इसका राज्य विधानमंडल राज्य सूची की मूल प्रविष्टि 54 में निहित विषय वस्तु पर एक नया कानून नहीं बना सका, फिर भी, अध्यादेश की मंजूरी, जिसने 02.07.2017 पर मौजूदा राज्य-कानून में संशोधन किया था, का प्रभाव मूल तिथि से संबंधित था जब वास्तव में इसे वैध रूप से संशोधित किया गया था। इसे उस तारीख तक कानून के पीछे के संबंध के सिद्धांत द्वारा समर्थित करने की कोशिश की जाती है जब अधिनियम बनाने की शक्ति मौजूद थी। समर्थन में तर्क यह था कि इसके प्रभाव अधिनियम के संदर्भ में विधायिका द्वारा कानून के अधिनियमन की तुलना में एक अध्यादेश [जो केवल एक अलग प्रक्रिया यानी कार्यकारी कानून बनाने का एक उत्पाद है] के बीच कोई अंतर नहीं है। एक अध्यादेश का जीवन सीमित हो सकता है,

लेकिन एक बार पारित या अधिनियमित होने के बाद, यह स्थायी हो जाता है। यहां तक कि जब यह लागू होता है, तब भी यह प्रभावी और विषय वस्तु पर बाध्यकारी होता है और राज्य एक अधिनियमित कानून के रूप में बाध्यकारी होता है। एक अध्यादेश के प्रभाव को ए. के. रॉय (ऊपर) में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया था:

“[.....] संविधान विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के बीच सैद्धांतिक रूप से कोई अंतर नहीं करता है। दोनों, समान रूप से, विधायी शक्ति के प्रयोग के उत्पाद हैं और इसलिए, दोनों समान रूप से उन सीमाओं के अधीन हैं जो संविधान ने उस शक्ति पर रखी हैं।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 198 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

197

99. आर. के. गर्ग आदि। आदि बनाम भारत संघ और अन्य 36 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

इसी तरह, वह अध्यादेश बनाने की शक्ति "की शक्ति के साथ सह-व्यापक है

संसद द्वारा कानून बनाना, यह देखना कठिन है कि राष्ट्रपति की इस विधायी शक्ति में किसी भी सीमा को कैसे पढ़ा जा सकता है ताकि कर कानूनों को बदलने या संशोधित करने के लिए इसे प्रभावी बनाया जा सके। यदि संसद कानून बनाकर कर कानूनों में बदलाव या संशोधन कर सकती है, तो समान रूप से राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके ऐसा कर सकते हैं।”

100. इस अदालत का मानना है कि तेलंगाना राज्य की दलीलें पर्याप्त नहीं हैं। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश उतना ही कानून है जितना कि राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कोई बाध्यकारी कानून। अंतर यह है कि कार्यपालिका की पारंपरिक भूमिका के विपरीत, कानून बनाना उसके प्राथमिक क्षेत्र के भीतर नहीं आता है। फिर भी संविधान कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने की आपातकालीन शक्ति प्रदान करता है जो एक सीमित अवधि के लिए काम कर सकते हैं जिसे राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष उसके अनुमोदन या अस्वीकृति के लिए अनिवार्य रूप से उठाया जा सकता है। अनुमोदन की स्थिति में, अध्यादेश को वह आकार दिया जाता है जिसमें विधायिका इसे अर्जित करती है। भारत में, प्रथा काफी हद तक प्रावधानों को अधिनियमित करने या विधेयक के रूप में प्रावधान अध्यादेश को शामिल करने की रही है जिसे तब राज्य विधानमंडल के सदनों या सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और फिर इसके परिणामस्वरूप एक अधिनियम बनता है। हालाँकि, राज्य का यह कहना सही है कि दोनों मामलों में कानून बनाना केवल आकार में है या दो अलग-अलग प्रक्रियाओं के उत्पाद हैं, फिर भी, इस पर रोक लगाना एक अति सरलीकरण होगा।

101. इस न्यायालय ने पिछले अवसरों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति के प्रभाव और उनके प्रभाव पर विचार किया था। इस मुद्दे पर कुछ परस्पर विरोधी निर्णय थे, विशेष रूप से इस बात पर कि क्या अध्यादेश के लागू होने के समय के दौरान किए गए किसी भी कार्य का प्रभाव बाध्यकारी और प्रभावी बना रह सकता है, भले ही वह बंद हो जाए या निष्क्रिय हो जाए, या दूसरे शब्दों में, समाप्त हो गया हो। चूंकि परस्पर विरोधी निर्णय मौजूद थे, इसलिए कृष्ण कुमार सिंह (ऊपर) में सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ ने मामले की विस्तार से जांच की। 5 न्यायाधीशों के बहुमत निर्णय की राय है कि किसी अध्यादेश के स्थायी प्रभाव के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया जा सकता है। कृष्ण कुमार सिंह (ऊपर) ने पहले एक अध्यादेश के प्रभाव को समझाया:

36 1982 (1) एससीआर 947

“क्या राज्य विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश रखने की आवश्यकता अनिवार्य है? इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। अभिव्यक्ति “रखी जाएगी” एक सकारात्मक जनादेश है जो कोई अपवाद नहीं है। यह कि अनुच्छेद 214 के खंड 2 के उपखंड (ए) में ‘होगा’ शब्द अनिवार्य है, प्रावधान को पूरी तरह से पढ़ने से निकलता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, एक अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। विधानमंडल के पुनः संयोजन के छह सप्ताह पूरे होने पर, एक अध्यादेश “काम करना बंद कर देगा”। दूसरे शब्दों में, जब विधानमंडल का सत्र फिर से शुरू होता है, तो घोषित अध्यादेश की एक शेल्फ लाइफ होती है जो विधानमंडल के इकट्ठा होने के छह सप्ताह बाद समाप्त हो जाती है। इसके बाद यह काम करना बंद कर देता है।”

इसके बाद वृहद पीठ राज्य विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश रखने की आवश्यकता की जांच करने के लिए आगे बढ़ी।

“31. राज्य विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश रखने से अध्यादेश बनाने की शक्ति पर विधायी नियंत्रण का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अध्यादेशों द्वारा कानून बनाना कानून बनाने का एक सामान्य स्रोत नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य विधायिका के अवकाश के दौरान एक आकस्मिक प्रकृति की असाधारण स्थितियों का सामना करना है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करते समय एक स्वतंत्र विधानमंडल का गठन नहीं करता है, लेकिन अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निर्वाचित विधायी निकाय के प्रति उत्तरदायी होती है जिसके प्रति सरकार उत्तरदायी होती है। संविधान अनुच्छेद 245 और 246 के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिनके बीच सातवीं अनुसूची में कानून के कुछ अंश वितरित किए गए हैं। राष्ट्रपति (अनुच्छेद 123 के तहत) और राज्यपालों (अनुच्छेद 212 के तहत) की अध्यादेश बनाने की शक्ति पर संसद और राज्य विधानसभाओं का संवैधानिक नियंत्रण लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायिका की सर्वोच्चता के लिए एक आवश्यक संगत है। विधानमंडल का पुनः संयोजन सत्र में इसकी अनुपस्थिति के दौरान घोषित अध्यादेश की वैधता के लिए बाहरी सीमा की अवहेलना करता है। उस अवधि के भीतर, एक विधायिका को अध्यादेश को अस्वीकार करने का अधिकार

है। विधायी निकाय के समक्ष एक अध्यादेश रखने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करती है कि अध्यादेश के प्रावधानों पर विधायिका में बहस और चर्चा की जाए। विधायिका के समक्ष 199 है।

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 200

विधायी शक्तियों का पूर्ण समूह और उन शक्तियों की एक घटना के रूप में, एक अध्यादेश को अस्वीकार करने का व्यक्त संवैधानिक अधिकार। यदि किसी अध्यादेश को अनुच्छेद 212 (2) (ए) द्वारा निर्धारित कार्यकाल से आगे जारी रखना है, तो उसके प्रावधानों को शामिल करते हुए विधायिका द्वारा एक कानून अधिनियमित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, हमारे संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि एक अध्यादेश केवल इसे अनुमोदित करने वाले प्रस्ताव के पारित होने पर राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के रूप को ग्रहण करेगा। अधिनियमित विधि के स्वरूप को अनुच्छेद 213 (2) (ए) द्वारा निर्धारित कार्यकाल से परे ग्रहण करने के लिए, एक विधि अधिनियमित की जानी चाहिए। विधायिका के समक्ष अध्यादेश को प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है; अंतर्निहित उद्देश्य और तर्क विधायिका को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाना है कि (i) अध्यादेश की आवश्यकता और समीचीनता; (ii) क्या कोई कानून बनाया जाना चाहिए; या (iii) क्या अध्यादेश को अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

32. राज्य विधानमंडल के समक्ष अध्यादेश रखने में विफलता अनुच्छेद 214 (2) द्वारा लगाए गए संवैधानिक दायित्व का गंभीर उल्लंघन है। यह सदन के समक्ष रखे जाने वाले एक अध्यादेश पर है कि इसे औपचारिक रूप से विधानमंडल के ध्यान में लाया जाता है। अध्यादेश रखने में विफलता एक गंभीर उल्लंघन है क्योंकि यह अध्यादेश से निपटने की विधायिका की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हम एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं दे रहे हैं कि विधायिका ऐसी स्थिति से नहीं निपट सकती है जहां सरकार ने अध्यादेश को विधायिका के समक्ष रखने के अपने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन किया हो। विधायिका निस्संदेह उस स्थिति में भी अनुच्छेद 214 (2) (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। हालांकि, राज्य विधानमंडल के समक्ष एक अध्यादेश रखने की आवश्यकता एक अनिवार्य दायित्व है और यह केवल निर्देशिका प्रकृति का नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे वर्तमान मामले में बिहार के राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों को लागू करने और फिर से लागू करने के लिए एक पैटर्न का पालन किया गया था, जिनमें से कोई भी राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखा गया था। इस तरह का आचरण शक्ति का एक रंगीन प्रयोग और संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग होगा। अब यह इस पृष्ठभूमि में है, और अब तक अनुच्छेद 214 के प्रावधानों की व्याख्या करने के बाद, इस विषय पर पूर्ववर्ती और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में बारीकियों का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

इस अदालत ने तब एक अध्यादेश के कानूनी प्रभावों की जांच की, यदि यह काम करना बंद कर देता है:

“58. फिर उन अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों या देनदारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है जो एक अध्यादेश के तहत उत्पन्न होते हैं जो काम करना बंद कर देता है? अनुच्छेद 214 (2) में दो आलोचनात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं जिनका बारीकी से विश्लेषण किया गया है। पहला यह है कि एक अध्यादेश का विधानमंडल के एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव होगा, जबकि दूसरा यह है कि यह विधानमंडल के पुनः संयोजन के छह सप्ताह की अवधि या अस्वीकृति के प्रस्ताव पर "काम करना बंद कर देगा"। "समान बल और प्रभाव होगा" अभिव्यक्ति की शुरुआत "इस अनुच्छेद के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश" शब्दों से की गई है। अनुच्छेद 213 के तहत जारी एक अध्यादेश का उल्लेख करते हुए, संविधान स्पष्ट रूप से यह अर्थ बताता है कि विधायी अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखने के लिए, अध्यादेश को अनुच्छेद 213 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसके अलावा "एक ही बल और प्रभाव होगा" अभिव्यक्ति के बाद "लेकिन ऐसा प्रत्येक अध्यादेश" उपखंड (ए) और (बी) में जो कहा गया है, उसके अधीन होगा। उद्घोषणा की शक्ति के वैध प्रयोग के लिए पूर्व-शर्तें और साथ ही उद्घोषणा के बाद की शर्तें दोनों एक समग्र योजना का हिस्सा हैं। 'समान बल और प्रभावी अधिनियम' खंड के संरक्षण के लिए एक अध्यादेश के लिए शर्तों के दोनों सेटों को पूरा करना होगा। एक बार जब यह निर्णय लागू हो जाता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि इसके कार्यकाल के दौरान, एक अध्यादेश उसी तरह से काम करेगा जैसे विधानमंडल का एक अधिनियम करता है। अनुच्छेद 212 (2) (ए) के प्रावधानों के आधार पर एक अध्यादेश का संचालन बंद होने का क्या परिणाम है? दो प्रतिस्पर्धी निर्माण हैं जो विचार के लिए आते हैं। "कार्य करना बंद कर देगा" पद का एक ओर यह अर्थ लगाया जा सकता है कि विधानमंडल के पुनः संयोजन के बाद या अध्यादेश की अस्वीकृति के बाद छह सप्ताह समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होने के साथ, यह उस तारीख से कार्य करना बंद कर देगा। 'इस अर्थ में काम करना बंद करने का मतलब यह होगा कि उस तारीख से प्रभावी होने के साथ, अध्यादेश का संभावित रूप से कोई संचालन नहीं होगा। यह अध्यादेश अपनी शुरुआत में अमान्य नहीं है। दूसरा अर्थ जो व्याख्या के लिए माना जा सकता है वह यह है कि अभिव्यक्ति "काम करना बंद कर देगी" का अर्थ यह होगा कि सभी कानूनी परिणाम

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 202 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

अध्यादेश के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने पर यह समाप्त हो जाएगा। दूसरे निर्माण के अनुसार, जो पहले से अधिक व्यापक है, एक अध्यादेश का संचालन बंद होने का परिणाम एक अध्यादेश की वैधता से संबंधित होगा।

59. अब, जिन विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उनमें से एक यह है कि अनुच्छेद 214 ने एक अध्यादेश के तहत उत्पन्न अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों या देनदारियों की बचत के लिए एक विशिष्ट सी प्रावधान नहीं किया है, जो तब से या तो अपनी अवधि समाप्त होने पर या

अस्वीकृति के संकल्प पर काम करना बंद कर चुका है।विशेष रूप से, संविधान के अन्य प्रावधान हैं, जहां संविधान ने किसी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले अधिकारों या देनदारियों को बचाने के लिए स्पष्ट प्रावधान किए हैं।”

अदालत ने तब पिछले फैसलों को खारिज कर दिया, जो "स्थायी अधिकार" सिद्धांत पर भरोसा करते थे और लागू करते थे, यह मानने के लिए कि अधिकार और विशेषाधिकार, अर्जित, या बनाए गए, और लगाए गए या मान लिए गए दायित्व जारी रहेंगे, भले ही अध्यादेश समाप्त हो जाए, या अमान्य हो जाए।यह माना गया था कि:

“68. [.....] भूपेंद्र कुमार बोस में निर्णय में स्वीकार किए गए स्थायी अधिकार सिद्धांत को एक अस्थायी अधिनियम की समाप्ति से उत्पन्न परिणामों से अलग किया गया था।उस सिद्धांत को अध्यादेश बनाने की शक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता है।अध्यादेश के संदर्भ में स्थायी अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां राज्यपाल द्वारा अधिकारों और विशेषाधिकारों, दायित्वों और देनदारियों के निर्माण के संदर्भ में शक्ति का प्रयोग इस परिकल्पना पर कायम रहेगा कि ये एक स्थायी चरित्र के हैं।विधायिका को अध्यादेश पर चर्चा या बहस करने का भी अवसर नहीं मिला होगा (जहां, वर्तमान मामले में, कोई भी अध्यादेश विधायिका के समक्ष नहीं रखा गया था); एक अध्यादेश को विशिष्ट रूप से अस्वीकृत किया गया हो सकता है या निर्धारित अवधि की समाप्ति पर काम करना बंद कर दिया हो सकता है।स्थायी अधिकार सिद्धांत स्थायी होने का श्रेय संसदीय नियंत्रण और सर्वोच्चता के अपमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को देता है।शक्ति प्रदान करने के संबंध में ऐसी कोई भी धारणा एस. आर. बोम्मई में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत होगी।

संविधान ने ऐसी स्थिति के संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया है जहां एक अध्यादेश को विधायिका के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है।ऐसी संभावना को ऐसी स्थिति के बराबर नहीं माना जा सकता है जहां एक अध्यादेश निर्धारित अवधि के बाद समाप्त हो जाता है या अस्वीकृत हो जाता है।यह आदेश कि अध्यादेश का संचालन बंद हो जाएगा, उन दो स्थितियों पर लागू होता है।विधायिका के समक्ष अध्यादेश को बिल्कुल नहीं रखना संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, संवैधानिक दायित्व का पालन करने में विफलता है।एक सरकार जो अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रही है और विधायिका तक पहुँचने में विफल रही है, वह वैध रूप से यह दावा नहीं कर सकती है कि वह जो अध्यादेश लाने में विफल रही है, वह तब तक वैध है जब तक कि उसका संचालन बंद नहीं हो जाता।अधिकारों और दायित्वों की एक इमारत को उन कार्यों पर संवैधानिक आदेश में नहीं बनाया जा सकता है जो सत्ता पर धोखाधड़ी के बराबर हैं।यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा।एक बार जब कोई अध्यादेश विधायिका के समक्ष रखा जाता है, तो वह संवैधानिक अधिनियम जिसके द्वारा उसके पास

अधिनियमित कानून के समान बल और प्रभाव होता है, अस्तित्व में आएगा और अध्यादेश की घोषणा से संबंधित होगा। विधायिका के समक्ष रखने की अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता के अनुपालन के अभाव में, संवैधानिक अधिनियम अस्तित्व में नहीं आएगा। वर्तमान मामले में, बिहार के राज्यपाल द्वारा घोषित किसी भी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखा गया था। यह संवैधानिक शक्ति के साथ धोखाधड़ी थी। संवैधानिक रूप से, किसी भी अध्यादेश का कोई बल या प्रभाव नहीं था। ध्यान देने योग्य तरीका विधायिका से बचना और विधायी नियंत्रण को समाप्त करना था। यह संवैधानिक प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग है। यह किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी परिणामों को जन्म नहीं देगा।”

102. वर्तमान मामले में, तेलंगाना अध्यादेश 17.6.2016 पर जारी किया गया था। तेलंगाना राज्य जी. एस. टी. अधिनियम अधिनियमित किया गया था और 25.05.2017 पर राज्यपाल की सहमति प्राप्त की गई थी; इसे 01.07.2017 पर लागू किया गया था। राज्य जी. एस. टी. अधिनियम में एक बचत और निरसन कानून शामिल था, जिसमें निरस्त अधिनियम, यानी राज्य वैट अधिनियम के तहत अर्जित कार्यों, विशेषाधिकारों और अधिकारों को बचाने की मांग की गई थी। यह तर्क दिया गया कि एक बार जब राज्य विधानमंडल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी और उसके अनुरूप संशोधन को अधिनियमित कर दिया, तो अध्यादेश के प्रावधान अधिनियम का हिस्सा बन गए। विधायी क्षमता का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि किसी अध्यादेश को केवल राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में सीमित करना होता है। चूंकि कानून को एक अलग प्रक्रिया के माध्यम से पेश किया गया था, यानी अध्यादेश, 203 का प्रभावी अधिनियम

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 204 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 15 एस. सी. आर.

वह कानून, जो वैट अधिकारियों को फिर से खोलने या मूल्यांकन को पूरा करने के लिए सशक्त बनाता है, कोई अलग नहीं था।

103. इस अदालत ने हाजी अब्दुल शुक्र (ऊपर) में फैसला सुनाया कि:

“राज्य विधानमंडल ऐसे कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है जिनका पूर्वव्यापी संचालन होगा। एक निश्चित पिछली अवधि के लिए कानून बनाने की इसकी क्षमता, इसकी वर्तमान विधायी शक्ति पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि इसके अधिनियमन के संचालन की अवधि में उसके पास क्या था। इसलिए हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं।

इस मामले को अलग तरीके से देखा जा सकता है। 1939 के अधिनियम के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। राज्य विधानमंडल 1963 में वही कर रहा था जो 1939 के अधिनियम को अधिनियमित करने वाले विधानमंडल को अधिनियमित करना चाहिए था और इसलिए इसका अधिनियमन 1952 के अधिनियम एल. आई. आई. की अवधि के दौरान अधिनियमित किए जाने वाले अधिनियम की संवैधानिक आवश्यकता द्वारा शासित नहीं था। अंत में, याचिकाकर्ता से यह आग्रह किया गया है कि खाल और खाल को अंतर-राज्यीय व्यापार या

वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित किया गया है।¹⁴ 1956 का केंद्रीय बिक्री कर।एस की उप-धारा (1) द्वारा अधिरोपित कर।² अधिनियम की धारा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान खाल और खाल की बिक्री पर एक कर है और इसलिए इसे सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 92 ए के भीतर रखा जाता है और इसलिए राज्य विधानमंडल इसे लागू करने के लिए सक्षम नहीं था।यह सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि संख्या 54 के आधार पर सूची 1 की प्रविष्टि संख्या 92 ए के प्रावधानों के अधीन माल की बिक्री या खरीद पर कर लगा सकता है।इस विवाद में कोई बल नहीं है।राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर कर लगाया जाता है।राज्य का कानून इस तरह का कर लगाने के लिए सक्षम है।केवल यह तथ्य कि राज्य में बेची गई वस्तु राज्य के बाहर से लाई गई थी, उस वस्तु की बिक्री को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री नहीं बनाता है।यह केवल तब होता है जब राज्य X में A, राज्य Y में एक कमीशन एजेंट के माध्यम से खरीदा जाता है और वाणिज्यिक एजेंसी के माध्यम से खरीदी गई वस्तुओं को प्राप्त करता है कि बिक्री 'अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान' अभिव्यक्ति के भीतर आती है: ब्रावणकोर कोचीन बनाम षण्मुघा विलास काजू कारखाने का राज्य देखें।(पृष्ठ 70 पर ऊपर दिया गया है)।

राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह अधिनियम कला के प्रावधानों से प्रभावित नहीं है।³⁰¹ संविधान के 304 के लिए क्योंकि वे भविष्य में कार्य करने के लिए अधिनियमों के संबंध में विधायी शक्ति प्रदान करते हैं और नहीं

ऐसे अधिनियमों को अधिनियमित करने की शक्ति जो अतीत में कार्य करेंगे।हम विवाद को ध्वनि नहीं मानते हैं।अधिनियम संविधान के प्रारंभ के बाद की अवधि के लिए प्रावधान करता है और इसलिए संविधान के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए।

इसलिए हमारा मानना है कि अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) आयातित खाल और खाल के खिलाफ भेदभाव करती है जो 1 अगस्त 1957 तक बेचे गए थे, जिस तारीख तक कच्चे खाल और खाल की बिक्री पर कर 3 पाई प्रति रुपये या 19/16th प्रतिशत की दर से था।तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि उप-धारा 1 अगस्त, 1957 के बाद हुई बिक्री के संबंध में मान्य है।उप-धारा एक निश्चित प्रारंभिक अवधि के संबंध में अपने प्रावधानों में शून्य होने के कारण, हम उस अवधि के लिए अधिनियमित अवधि के संबंध में प्रावधान को नहीं बदल सकते हैं जिसके लिए यह वैध हो सकता है क्योंकि वह अधिनियम को फिर से लिखना होगा।इसलिए हमें उस उप-को धारण करना होगा।(1) धारा 2 तदनुसार शून्य मानती है।”

104. इस न्यायालय द्वारा जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य 37 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

“विधायी अधिनियम के लिए चुनौती केवल तभी स्थायी होगी जब यह स्थापित हो जाए कि संबंधित विधायिका के पास उस विषय पर अधिनियमित करने की कोई विधायी क्षमता नहीं थी जिसे उसने अधिनियमित किया है।”

105. तेलंगाना राज्य ने इसके विपरीत तर्क दिया था, और समझाया था कि जब अध्यादेश जारी किया गया था, तो राज्य के विधायी क्षमता रखने के बारे में कोई संदेह नहीं था। उस तारीख तक (17.06.2017) मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की शक्ति, संशोधन की धारा 19 के तहत अनुमत थी। हालाँकि, यह तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि अध्यादेश की वैधता और प्रभाव इसकी घोषणा की तारीख को संदिग्ध नहीं रहा होगा; फिर भी, मुद्दा यह है कि जिस तारीख को इसे वास्तव में अनुमोदित किया गया था और एक संशोधन के रूप में आकार दिया गया था, उस तारीख को राज्य विधानमंडल के पास शक्ति नहीं थी। उस समय तक, राज्य जी. एस. टी. और केंद्रीय जी. एस. टी. अधिनियम (01.07.2017 पर) लागू हो चुके थे। इसलिए, धारा 19 प्रभावी होना बंद हो गई। मूल प्रविष्टि (राज्य सूची की प्रविष्टि 54) का अस्तित्व समाप्त हो गया। इन परिस्थितियों में, राज्य विधानमंडल में कोई विधायी व्यवस्था नहीं थी।

37 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 813 205

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 206

संशोधन को अधिनियमित करने की क्षमता, जिसने अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसे परिणामस्वरूप अमान्य कर दिया गया।

106. एक सहायक तर्क यह था कि अध्यादेश के अनुसरण में किए गए कार्य समाप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे राज्य जी. एस. टी. अधिनियम के निरसन और बचत खंड (धारा 174 38) के आधार पर सुरक्षित हैं, अध्यादेश के अनुसार की गई सभी कार्रवाई, जब यह लागू था, को बचाया जाएगा। इस अदालत की राय में, उस तर्क में कोई योग्यता नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन की अयोग्यता (जो <आई. डी. 1 पर अध्यादेश के अनुरूप थी) राज्य जी. एस. टी. के संशोधित प्रावधानों के तहत कार्य करने वालों के अधिकार क्षेत्र की जड़ों में चली गई, जिससे वे (वास्तव में, मूल प्रावधान) अमान्य और अप्रवर्तनीय हो गए। इसके अलावा, भले ही किसी कारण से, अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार शुरू किए गए किसी भी नोटिस या कार्यवाही की वैधता और निरंतरता के बारे में कोई संदेह था, उनकी अयोग्यता ऐसी है कि उन्हें बनाए नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, जैसा कि कृष्ण कुमार सिंह (उपरोक्त) में कहा गया है, जब तक कि परिणाम "अपरिवर्तनीय" नहीं हैं, तब तक संविधान के प्रावधानों के संचालन के कारण किसी अध्यादेश के तहत की गई किसी भी कार्रवाई को जारी रखने का आम तौर पर कोई सवाल ही नहीं है। यद्यपि इस न्यायालय की टिप्पणियां विधानमंडलों के सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण समाप्त होने वाले अध्यादेशों के संदर्भ में थीं, लेकिन इस न्यायालय के सुविचारित विचार में, वही सिद्धांत उन मामलों पर लागू होगा, जहां विषय वस्तु पर विधानमंडल की क्षमता समाप्त हो जाती है।

107. इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि स्थानीय वैट अधिनियम में संशोधन करने वाले बाद के राज्य अधिनियम द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के प्रावधान वैध हैं।

D. गुजरात और महाराष्ट्र अधिनियम

108. गुजरात वैट अधिनियम के मामले में, संक्षिप्त तथ्य यह है कि वाणिज्यिक कर के उपायुक्त ने एक मूल्यांकन आदेश पारित किया

38 अन्य बातों के साथ-साथ धारा 174 (2) का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:“(2) उप-धारा (1) या धारा 173 में उल्लिखित सीमा तक उक्त अधिनियमों का निरसन और धारा 173 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों का संशोधन (इसके बाद, यथास्थिति, ऐसा संशोधन या संशोधित अधिनियम के रूप में संदर्भित)-(ए) ऐसे संशोधन या निरसन के समय लागू या विद्यमान किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित नहीं करेगा या (बी) संशोधित अधिनियमों या निरस्त अधिनियमों और आदेशों या उसके तहत विधिवत किए गए या पर्याप्त किए गए किसी भी चीज़ के पिछले संचालन को लागू नहीं करेगा; या (सी) ऐसे निरस्त या संशोधित अधिनियमों के तहत संशोधित अधिनियमों या निरस्त अधिनियमों या आदेशों के तहत अर्जित, अर्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को लागू नहीं करेगा:”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

23 दिसंबर, 2009 को वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के खिलाफ आई. डी. 1 लगाया गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट को आठ प्रतिशत तक उलट दिया गया।, अर्थात्, गुजरात वैट अधिनियम की धारा 11 (3) (बी) (ii) और 11 (3) (बी) (iii) के प्रत्येक प्रावधान के तहत चार प्रतिशत। अपीलीय प्राधिकारी ने निर्धारिती को बर्खास्त कर दिया। 26 अप्रैल, 2012 को गुजरात वैट न्यायाधिकरण ने बिक्री कर अधिकारियों के दोनों आदेशों को रद्द करके और यह मानते हुए कि खरीद के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट में आठ प्रतिशत की कमी शाखा हस्तांतरण लेनदेन की खेप पर लागू नहीं थी, निर्धारिती की दूसरी अपील को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने 18 जनवरी, 2013 के निर्णय 39 द्वारा वैट न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 11 (3) (बी) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट में कमी किसी भी मामले में चार प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 11 (3) (बी) के तहत प्रदान की गई कर क्रेडिट का लाभ उठाने की सीमा केवल एक बार लागू की जा सकती है, भले ही इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या खरीदी गई विशेष वस्तु वैट अधिनियम की धारा 11 (3) (बी) के एक से अधिक उपखंडों में आती है। संबंधित अधिकारी द्वारा दो अलग-अलग मुद्दों के लिए एक मूल्यांकन आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले को कर अधिकारियों द्वारा प्रभावी बनाया गया था। वैट न्यायाधिकरण के एक निर्णय में, एक अन्य मामले में प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया था कि देश के बाहर निर्यात की जाने वाली कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की खरीद पर निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाना था। दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण के अनुसार, उक्त प्रोत्साहन सीमा को निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए उक्त कर द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। इन निर्णयों को उच्च न्यायालय 40 द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। उस फैसले को ध्यान में रखते हुए, आयुक्त ने वैट अधिनियम की धारा 75 के तहत मार्च, 2018 में एक संशोधन नोटिस जारी किया, कि उन्हें दिए गए लाभ को उच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी बनाने के लिए संशोधित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

109. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को लागू किया गया था। वे 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी अधिनियम के साथ लागू हुए। 20 सितंबर, 2016 को वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त ने एक आदेश पारित किया और याचिकाकर्ता-कंपनी के मामले में बिक्री कर प्रोत्साहन को कम कर दिया।

39 गुजरात राज्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2013] 58 वीएसटी 376 (गुजरात); 2013 एससीसी ऑनलाइन गुज 8788

40 गुजरात राज्य बनाम वेलस्पन गुजरात स्टाल रोरेन लिमिटेड [2014] 71 वीएसटी 550 (गुजरात); 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुज 15909 207

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 208

कर योग्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली कर योग्य वस्तुएँ, जो देश के बाहर निर्यात की जाती हैं। 1 जुलाई, 2017 को दो कानून, अर्थात् गुजरात वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, राज्य के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की सभी आपूर्ति या दोनों पर कर लगाने के लिए लागू हुए। गुजरात मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 को गुजरात मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 के आधार पर इसके कई प्रावधानों को प्रतिस्थापित और हटा कर काफी हद तक संशोधित किया गया था। यह 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी अधिनियम के साथ लागू हुआ। इस बीच, उच्च न्यायालय ने राज्य के नेतृत्व में एक अपील में 22 सितंबर, 2017 को एक आदेश पारित किया, जिसमें 18 जनवरी, 2013 के फैसले 41 को रद्द कर दिया गया।

110. इस अदालत के उपरोक्त फैसले को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक कर के अतिरिक्त आयुक्त ने इस अदालत के 22 सितंबर, 2017 के फैसले के आलोक में वैट अधिनियम की धारा 11 (3) (बी) (ii) और 11 (3) (बी) (iii) के प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को आठ प्रतिशत तक कम करने के लिए 30 मार्च, 2013 (क्रम संख्या 5) के आदेश द्वारा किए गए वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यांकन आदेश को संशोधित करने के लिए अधिनियम की धारा 75 के तहत फॉर्म 503 में 3 नवंबर, 2017 को एक संशोधन नोटिस जारी किया। पुनरीक्षण नोटिस 42 को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।

111. वैट (संशोधन) अधिनियम, 2018 के आधार पर, वैट अधिनियम में धारा 84 ए को 1 अप्रैल, 2006 से पूर्वव्यापी रूप से लागू करने के लिए जोड़ा गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, गुजरात वैट अधिनियम की धारा 75 में निर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना में अपीलीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख के बीच बिताई गई अवधि को हटाने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान मामले में, 18 जनवरी, 2013 के उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से शुरू होने वाली अवधि 43 इस न्यायालय के निर्णय की तारीख, यानी 22 सितंबर, 2017 44 तक के राजस्व के खिलाफ प्रदान की गई। इसके

परिणामस्वरूप, 1 सितंबर, 2018 को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा संशोधन के लिए नया नोटिस जारी किया गया था।

41 गुजरात राज्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [2017] 16 एससीसी 28.

42 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम के मामले में निर्णय में गुजरात राज्य [2018] 58 जीएसटीआर 366 (गुज))

43 2012 की कर अपील संख्या 934 और 935 में उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2013

44 गुजरात राज्य बनाम रिलायंस इंडस्ट्रीज में इस अदालत का आदेश। 2017 की सिविल अपील संख्या 13047-13048।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

30 मार्च, 2013 के आदेश द्वारा किए गए वित्तीय वर्ष 2008-09 के निर्धारण को संशोधित करने के लिए उपरोक्त संदर्भित नई जोड़ी गई धारा 84 ए के आधार पर निर्धारिती को वाणिज्यिक कर। नोटिस जारी करने के लिए गुजरात वैट अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रदान की गई सीमा की मूल अवधि मूल्यांकन आदेश की तारीख से तीन साल की थी, यानी 30 मार्च, 2013, जो 30 मार्च, 2016 को समाप्त हो गई थी। हालांकि, नव अधिनियमित धारा 84 ए के आधार पर, उच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से इस न्यायालय के निर्णय की तारीख तक बिताई गई अवधि को गुजरात वैट अधिनियम की धारा 75 के तहत संदर्भित तीन साल की उपरोक्त अवधि की गणना में शामिल नहीं किया जाना था। इस विकास के परिणामस्वरूप संशोधन की वैधता को चुनौती मिली। राज्य ने आग्रह किया था कि एक मान्यकारी अधिनियम होने के नाते, जो पहले पाए गए दोष को ठीक करने का प्रयास करता है, और यह देखते हुए कि यह पूर्वव्यापी रूप से संचालित होता है, संशोधन के अमान्य होने का कोई सवाल ही नहीं है।

112. निस्संदेह इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जैसे कि

श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम ब्रोच बरो नगरपालिका 45 आंध्र प्रदेश सरकार बनाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड 46; उजागर प्रिंट्स बनाम.

भारत संघ 47 और कई अन्य, जो मानते हैं कि एक विशुद्ध रूप से उपचारात्मक और मान्यकारी अधिनियम, यदि पूर्वव्यापी बनाया जाता है, तो असाधारण है। हालांकि,

यह इस अदालत द्वारा केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड 48 में अभिनिर्धारित किया गया है:

“..... 1910 के अधिनियम के साथ-साथ 1948-अधिनियम दोनों मौजूदा कानून हैं जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत विचार किया गया है। एक मौजूदा कानून अभी भी वैध है, भले ही मौजूदा कानून के विषय-वस्तु के संबंध में विधायी शक्ति संविधान के तहत उस सूची से अलग सूची में हो, जिसके तहत यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत आती। लेकिन

संविधान लागू होने के बाद एक मौजूदा कानून को केवल विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता था जो उस कानून को लागू करने के लिए सक्षम होगा यदि इसे नया अधिनियमित किया जाना था।

45 1970 (1) एससीआर 388

46 [1975] सप्लीमेंट (1) एससीआर 394 47 [1988] सप्लीमेंट 3 एससीआर 770 48 [1976] 1 एससीआर 552 209

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 210

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रामकृष्ण रामनाथ (उपर्युक्त) का मानना था कि निरस्त करने की शक्ति संशोधन करने या कानून बनाने की शक्ति के साथ-साथ व्यापक है। यह था।

यह भी माना गया कि "(टी) शक्ति को उस समय देखा जाना चाहिए जब निरस्तीकरण कानून लागू किया जा रहा है। [...] हालाँकि, विधानमंडल के पास उस समय क्षमता होनी चाहिए जब इस तरह का निरसन कानून लागू किया जा रहा हो।"

113. वर्तमान मामले में, 2006 से प्रभावी अधिनियम के साथ लागू किए गए संशोधन को दिया गया पूर्वव्यापी प्रभाव, इसे किसी भी तरह से, जी. एस. टी. कानूनों के लागू होने के बाद, 01.07.2017 पर नहीं बचा सकता है। न ही इस बात का कोई तर्क हो सकता है कि फरवरी, 2018 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 246 ए का पता लगाने योग्य है। इस पहलू पर, इस न्यायालय ने यूनियन में निर्णय दिया

भारत बनाम मोहित खनिज प्राइवेट लिमिटेड 49. कि " अनुच्छेद 246 ए में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति' है। इस प्रकार, कानून बनाने की शक्ति सामान्य प्रविष्टि से संबंधित सामान्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह विशेष रूप से वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। जब वस्तु और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने के लिए व्यक्त शक्ति होती है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि इस शक्ति में वस्तु और सेवा कर पर उपकर लगाने की शक्ति कैसे शामिल नहीं होगी। यह सच है कि संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 को विभिन्न करों, अधिभारों और उपकरों को एक कर में समाहित करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन संवैधानिक प्रावधान से यह संकेत नहीं मिलता है कि अब से कोई अधिभार या उपकर नहीं लगाया जाएगा।"

114. जहां तक महाराष्ट्र की अपीलों का संबंध है, निर्धारिती की शिकायत है कि महाराष्ट्र वैट अधिनियम में किए गए पूर्वव्यापी संशोधन अमान्य थे। आई. डी. 1 पर, राज्य ने महाराष्ट्र कर कानून (शुल्क, संशोधन और वैधता) अधिनियम 2017 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया, जिससे विभिन्न अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया गया। एम. वी. ए. टी. अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद संख्या 26 में धारा 6 (ए), 6 (बी) और 6 (सी) को जोड़ा गया था। इनके प्रभाव के लिए विवादित कर देयता के 10 प्रतिशत की अनिवार्य पूर्व-जमा राशि की आवश्यकता थी। इसे चुनौती दी गई थी और बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने अंशुल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम राज्य

महाराष्ट्र 50 (इसके बाद, "अंशुल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड") ने

2011 में शुरू हुए आई. एस. पर लागू नहीं होने वाला संशोधन।राज्य ने एक बार फिर

49 2018 (13) एससीआर 139

50 28 सितंबर, 2018 को दिए गए निर्णय में एस. टी. ए. सं. 2/2018

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में संशोधन किया गया, अर्थात् महाराष्ट्र अध्यादेश सं। 2019 का VI, 6 मार्च, 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अध्यादेश द्वारा महाराष्ट्र राज्य ने 15 अप्रैल 2017 से एक स्पष्टीकरण जोड़ा।राज्य के अनुसार, अंशुल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में अदालत की नागपुर पीठ के फैसले को देखते हुए संदेह को दूर करने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। 9 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र कर कानून (शुल्क, संशोधन और वैधता) अधिनियम 2019 लागू किया गया था। इसे 9 जुलाई 2019 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अध्यादेश के स्थान पर एम. वी. ए. टी. अधिनियम, 2002 की धारा 26 (6 सी) के उक्त स्पष्टीकरण सहित विभिन्न प्रावधानों को शामिल करते हुए राज्य विधानमंडल का अधिनियमन किया गया। स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट करने का प्रभाव था कि जमा करने से पहले की आवश्यकताएं 2017 से पहले की अपीलों और संशोधनों पर लागू होती थीं। इसे चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने एक पूर्ण पीठ के फैसले 51 द्वारा संशोधन को बरकरार रखा। यह माना गया कि

“राज्य सरकार के पास निर्णय की नींव के आधार को पूर्वव्यापी रूप से हटाने की विधायी क्षमता है। राज्य सरकार को किसी भी निर्णय में न्यायालय द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने और न्यायालय द्वारा घोषित कानून के साथ असंगत कानून में संशोधन करके उचित वाक्यांश का उपयोग करके कानून में संशोधन करने के लिए उपयुक्त संशोधन करने का अधिकार है ताकि जो दोष बताए गए थे वे कानून के प्रभावी प्रवर्तन के लिए कानून में कभी न हों। राज्य सरकार द्वारा संशोधन को सम्मिलित करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई न्यायिक अतिक्रमण नहीं है जो इन याचिकाओं का विषय है जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रचार किया जाना चाहिए।

.हमारे विचार में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी निर्णय या सरलीकरणकर्ता के माध्यम से ऐसे दोषों को दूर करने के माध्यम से बताए गए दोष को ठीक करना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अतिक्रमण करने या न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को खारिज करने या न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रभाव को रद्द करके राज्य सरकार की शक्तियों का अतिक्रमण करने के बराबर नहीं है।”

115. इस न्यायालय की राय में, इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि एक विधायी निकाय एक उपचारात्मक कानून बनाने के लिए सक्षम है

51 संयुक्त परियोजना बनाम महाराष्ट्र राज्य (रिट याचिका (एसटी)) 2021 की संख्या 11589 और 2018 की रिट याचिका संख्या 13754 ने 12.07.2022 211 पर निर्णय लिया

तेलंगाना राज्य और ओ. आर. एस. बनाम मेसर्स तिरुमाला कंस्ट्रक्शंस [एस. रवींद्र भाट, जे.] 212

पूर्वव्यापी प्रभाव ^{ect}। फिर भी, वही दोष जो खुद को गुजरात संशोधन से जोड़ता है, अर्थात् संशोधन के अधिनियमित होने की तारीख को योग्यता की कमी, यानी इस मामले में, महाराष्ट्र विधानमंडल का विषय वस्तु पर कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मूल प्रविष्टि 54 में पर्याप्त परिवर्तन हुआ था, और वैट अधिनियम को बदलने की शक्ति समाप्त हो गई थी, जब जी. एस. टी. व्यवस्था प्रभावी हुई। इसलिए, उन्हीं कारणों से, अन्य मामलों की तरह, महाराष्ट्र वैट अधिनियम में संशोधन नहीं रह सकते हैं।

VI. निष्कर्ष

116. पूर्वगामी चर्चा और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों में न्यायालय के निर्णय इस प्रकार हैं:

(i) संविधान (101 वां संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 19 और घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित अनुच्छेद 246 ए, इसके संचालन की सीमित अवधि के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था का हिस्सा थे, और इसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि (ओं) के लिए असंगत कानूनों के संचालन को जारी रखने का प्रभाव था और इसके संचालन के आधार पर, राज्य विधानसभाओं और संसद को ऐसे मौजूदा कानूनों में संशोधन या निरसन करने की अनुमति दी गई थी।

((ii) चूंकि उक्त संशोधन अधिनियम के अन्य प्रावधानों में (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की) सूची I और सूची II से विधान के शीर्षों को हटाने का प्रभाव था, इसलिए धारा 19 और अनुच्छेद 246 ए दोनों ने इस घटक अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित किया कि मौजूदा कानून जारी रहेंगे और उनमें संशोधन किया जा सकता है। कानून के स्रोत या अन्य तथ्य, जिस हद तक उन्हें दोनों सूचियों से हटा दिया गया था, कुछ समय के लिए, धारा 19 में निहित थे। नतीजतन, संशोधन करने की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी।

(iii) उपरोक्त निर्णय 101 वें संशोधन के लागू होने से उत्पन्न रिक्तता को ध्यान में रखते हुए है, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त दो सूचियों में विधान के प्रमुखों को हटा दिया गया है।

(iv) तेलंगाना वैट अधिनियम और गुजरात वैट अधिनियम में किए गए संशोधनों को दो उच्च न्यायालयों (तेलंगाना और गुजरात उच्च न्यायालय) द्वारा विधायी क्षमता के अभाव में अमान्य ठहराया गया था। का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

बॉम्बे उच्च न्यायालय को, उपरोक्त कारणों से, त्रुटिपूर्ण माना जाता है; इसे दरकिनार कर दिया जाता है; महाराष्ट्र अधिनियम में संशोधन, जिस हद तक पूर्व-जमा की आवश्यकता होती है, उसे अमान्य माना जाता है।

117. तेलंगाना और गुजरात राज्यों के नेतृत्व में की गई अपीलों (और किसी भी अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं) को उपरोक्त शर्तों में खारिज कर दिया जाता है। बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय (अर्थात् सिविल अपील सं. 2730-2733/2023 और एस. एल. पी. (सी) सं. 7776/2023) के विरुद्ध निर्धारिती की अपील सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है।लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान